सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 126, नई दिल्ली । बुधवार, 17 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने किरदार की हिफाजत जान से बढ़कर कीजिये, क्योंकि इसे जिंदगी के बाद भी याद किया जाता है।

03 2024-लोकसभा चुनाव हारे 200 सांसदो को सरकारी बंगले खाली करने के थमाए नोटिस

06 नए बजट में रोजगार सृजन पर हो जोर

08 ओडिशा ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की

सिर्फ कुछ महीने शेष :- दिल्ली परिवहन विभाग की कार्य श्रेणी तकनीकी से गैर तकनीकी में जाएगी बदल

दिल्ली परिवहन विभाग में एक और तकनीकी अधिकारी द्वारा की गई वीआरएस की मांग

संजय बाटला

नई दिल्ली। अगर यही हालात और आला अधिकारियों की कार्यशैली रही तो कुछ ही महीनों में दिल्ली परिवहन विभाग तकनीकी अधिकारी द्वारा नही गैर तकनीकी अधिकारियों/ कर्मचारियों के द्वारा दुनिया का पहला संचालित राजकीय परिवहन कार्यालय की उपाधि प्राप्त कर लेगा। **भारत सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली और मुख्य सचिव दिल्ली की जानकारी में होते हुए और कानून/ नियम के साथ न्यायिक दिशा निर्देश होने के बावजूद इतना बड़ा फैसला और सबकी आंख, कान और मुंह बंद, यहां तक उच्च न्यायालय दिल्ली/उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा भी नही लिया गया संज्ञान,**

लगता है न्यायिक प्रणाली और प्रवर्तन शाखाएं (**पुलिस, विजिलेंस, एंटी करप्शन, सीबीआई**) भी सभी

तकनीकी पदो पर गैर तकनीकी अधिकारियों को कार्यरत देखने के लिए लालायित हैं। **दिल्ली परिवहन विभाग तो सिर्फ इसके प्रति एक उदाहरण बनने का श्रेय प्राप्त कर रहा है और इस श्रेय को दिलवाने में सबसे अधिक हिम्मत पूर्व आयुक्त एवम्तत्काल में प्रमुख सचिव उपराज्यपाल आशीष कुंद्रा, विशेष आयुक्त के के दहिया, तत्काल आयुक्त परिवहन प्रशांत गोयल और विशेष आयुक्त शहजाद आलम को जाता है। इन चारों अधिकारियों ने अपनी हिम्मत और कार्यशैली की बदौलत दुनिया के समक्ष यह सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी की तकनीकी और गैर तकनीकी अधिकारी में कोई अन्तर हैं।** इन की मानी जाए तो परिवहन विभाग में तकनीकी अधिकारी से बेहतर कार्य गैर तकनीकी अधिकारी तकनीकी पद पर आसीन होकर कर सकता हैं। इन की नजर में (**एस.ओ**) अनुभाग अधिकारी और (**एस.ओ.**) सांख्यिकी अधिकारी परिवहन विभाग के तकनीकी पद पर तकनीकी अधिकारी एम. वी. आई. जो परिवहन के प्रति तकनीकी डिग्री प्राप्त कर कार्य नही कर सकता वह कार्य उनसे अधिक कुशलता से कर सकते है। *अब जानना यह आवश्यक है की जब तकनीकी कार्य बिना तकनीक की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति कर सकता हैं जैसा उपरलिखित नामों और पदो पर आसिन अधिकारियों द्वारा तकनीकी पदो पर सख्यिकी अधिकारी और अनुभाग अधिकारी को नियुक्त कर करवाना शुरु किया तो तकनीकी संस्थाओं की आवश्यकता ही क्यों ?

फिर तो

ना मेडिकल कालेज की जरूरत है और ना ही आई टी इत्यादि की, झोला छाप व्यक्ति इलाज कर सकता हैं फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों अगर इन अधिकारियों द्वारा दिए गए और लिए गए निर्णय सही तो फिर बाकी गलत क्यों?

21 जुलाई की आधी रात से लागू हो जाएगा भारी वाहनों का डाइवर्जन

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद। कांवड़ यात्रा के लिए 21 जुलाई की आधी रात से भारी वाहनों का डाइवर्जन लागू हो जाएगा। यह प्लान पांच अगस्त की रात आठ बजे तक जारी रहेगा। यातायात पुलिस ने 12 बिंदुओं पर डाइवर्जन प्लान बनाया है। यातायात पुलिस शीघ्र ही हल्के वाहनों के लिए भी डाइवर्जन प्लान जारी करेगी। शहर के प्रवेश स्थानों से भारी वाहनों को अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर गंतव्य तक जाना होगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को अनुमति के बाद सर्शत डाइवर्जन से छूट रहेगी। डाइवर्जन लागू होने वाले स्थानों पर पुलिस सांकेतिक बोर्ड वाहन चालकों की सुविधा के लिए लगाएगी। कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर डाइवर्जन प्लान में बदलाव भी किया जा सकता है।

भारी वाहनों के लिए यह रहेगा डाइवर्जन

दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों का (तुलसी निकेतन बॉर्डर, सीमापुरी बॉर्डर, आनन्द विहार बॉर्डर) का गाजियाबाद शहर में प्रवेश प्रतबंधित रहेगा। ऐसे सभी वाहन गाजीपुर बॉर्डर से यूपी गेट होते हुए एनएच-नौ पर गंतव्य तक जाएंगे।

दिल्ली की ओर से आने वाले वाहन जिन्हें हरिद्वार अमरोहा, मुरादाबाद, लखनऊ आदि स्थानों पर जाना है, गाजीपुर बॉर्डर से यूपी गेट होते हुए एनएच-नौ पर डासना से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होते हुए अपने गंतव्य को जाएंग।

बागपत की ओर से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन ट्रोनिका सिटी, सोनिया विहार होते हुए जाएंगे।

हापुड़, बुलंदशहर की तरफ से आने वाले वाहन डासना पुल से सीधे गाजियाबाद शहर की और न आकर एनएच-नौ का प्रयोग करते हुए जाएंगे।

बुलंदशहर, हापुड़ की तरफ से आने वाले वाहन लाल कुआं से सीधे गाजियाबाद शहर की ओर न आकर एनएच-नौ का प्रयोग करते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।

दिल्ली, हापुड़, लालकुआं की ओर से आने वाले वाहन आत्माराम स्टील प्लांट तिराहा से शहर की ओर न आकर एनएच-नौ का प्रयोग करते हुए जाएंगे।

लोनी बॉर्डर से लोनी कस्बे की ओर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

संतोष मेडिकल कट से मेरठ तिराहा की तरफ भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

गौर ग्रीन एवेन्यू, खोड़ा, काला पत्थर, नोएडा सेक्टर-62, छिजारसी, कनावनी पुस्ता से एनएच-नौ होते हुए इंदिरापुरम क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग, पाइप लाइन मार्ग, दिल्ली मेरठ रोड व दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

हापुड़, भोजपुर से आने वाले वाहनों का मोदीनगर की ओर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

वसुंधरा फ्लाई ओवर से मोहननगर की ओर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

हेल्पलाइन नंबर
नगर नियंत्रण कक्ष - 9643208942
लैंडलाइन नंबर- 0120-2989100
ग्रामीण नियंत्रण कक्ष - 8929436700
लैंडलाइन नंबर- 0120-2764999
ट्रांस हिंडन नियंत्रण कक्ष - 9643204440

गुरुग्राम-फरीदाबाद टोल: बढ़ती नाराजगी के बीच यात्रियों की मांग - "टोल हटाओ"

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम-फरीदाबाद मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा पर प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सुबह और शाम के कार्यालय समय में यहां लगातार जाम लग रहा है, जिससे यात्री परेशान हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर यात्रियों ने अपनी समस्याओं को साझा किया है और गूगल रिव्यूज पर 1 से 2 रेटिंग देकर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

कारों के लिए टोल की दर 45 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई है, लेकिन सेवा स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस भारी बढ़ोतरी और खराब सेवा ने यात्रियों में नकारात्मक प्रभाव डाला है और अब वे टोल को पूरी तरह से हटाने की मांग कर रहे हैं।

यात्रियों ने संबंधित पीडब्ल्यूडी और यातायात प्राधिकरण को ईमेल भेजे हैं और फरीदाबाद और गुड़गांव के अधिकारियों से इस समस्या के समाधान की मांग की है। कुछ यात्रियों ने नियमित जाम की शिकायतें दर्ज करवाई हैं और 112 पर भी फोन किया है। यह स्थिति न केवल रोड रेज बल्कि गहरी सड़क सुरक्षा चिंता का कारण भी बन रही है।

#VocalForLocalToll सर्वेक्षण: टोल सेवाओं और प्रबंधन पर नाराजगी

एक हालिया #VocalForLocalToll सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकांश यात्रियों ने टोल सेवाओं और प्रबंधन से नाराजगी जताई है। सर्वेक्षण के अनुसार, अधिकतर लोग टोल को हटाने की मांग कर रहे हैं।

यह स्क्रीनशॉट सर्वेक्षण में प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है:

सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और यात्रियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना चाहिए। टोल की दरों में कमी और सेवा सुधार के बिना, यात्रियों का गुस्सा और बढ़ सकता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है।

सड़कों पर रेहडियां, कार डीलर्स की खडी कारें, जाम के बीच, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, विक्लाग सब हैं हैरान

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। सडक सुरक्षा को लेकर ,सरकारी फरमान, डिबेट, अभियानो के बीच ट्रैफिक जाम, सडकों पर रेहडी, पार्क की गई गाडियां तो ये ही संदेश दे रही है कि करोडों का बजट फूंकने के बाद भी राजधानी दिल्ली समेत देशभर में ट्रैफिक से जुडी परेशानियां अपनी बाहें फैलाए भीचने को बेताब है।

इस बावत इमानदारी से नजर दौडाई जाए तो नजरें आकर ढुलमुल ट्रैफिक व्यवस्था पर आ टिकती है। दरअसल जिनके कंधो पर ट्रैफिक व्यवस्था की कमान सौंपी गई है ,लगता हैं पूरा ढांचा ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है ।ले देकर कुछ इमानदारी से काम करने वालों को महकमा ही किनारे लगाने को हमेशा तैयार रहता है। बढते सडक हादसों को रोकने के लिए बनी एजेंसिया ही बडा कारण है।

जो चंद पैसो की खातिर सब कुछ देखते होते हुए भी आंखे मूंदे बैठे हैं। आम जनता का आरोप है कि फुटपाथ और ,सडकों पर कब्जा, अवैध उगाही का बहुत बडा कारण है। ट्रैफिक व्यवस्था में जुटी जिम्मेवार ट्रैफिक पुलिस कानून का हवाला देकर मोटी कमाई कर रही है। इसमें इलाकई पुलिस का भी बहुत बडा रोल है। मुख्य सडको के दोनों तरफ अवैध गाडियां की पार्किंग महीना वसूली के चलते परमानेंट खडी रहती है। फुटपाथ दुकान वालों ने कब्जा लिया है।अब बच्चे बूढे,महिलाए विक्लांगों को मजबूरी में चलती ट्रैफिक के बीच से होकर गुजरना पड रहा है। इस वजह से आए दिन एक्सीडेंट की घटनाए बढ रही है। इससे जाहिर है कि सडक सुरक्षा,को लेकर नागरिको की सेफ्टी के प्रति गैरजिम्मेदार एजेंसिया ही जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पर अवंतिका,रोहिणी चौराहे से जयपुर गोल्डन अस्पताल वाली सडक को कार डीलरों ने कब्जा रखा है। महज 5-6 फुट की कार डीलर्स की प्रत्येक दुकान के आगे सडक पर 15-20 गाडियां 24 घंटे खडी रहती है। इससे अक्सर

टैफिक स्मुथ आने -जाने में जाम का सामना करना पडता है।वहीं किसी ने समान या बैंक में काम से कार पार्किंग की है तो ट्रैफिक पुलिस की क्रेन कार को टॉचन करके ले जाती है। वहां भी कार छुडाने के लिए मोटी रकम ऐठी जाती है।बच्चों की स्कूल कैब वालों से हफ्ता बंधा हुआ है।

ट्रैफिक पुलिस के कारिंदे ने लाल बत्ती चौराहे पर अपना आदमी वसूली के लिए बाकायदा खडा किया हुआ है,जो पैसा इक्ट्ठा करके ट्रैफिक पुलिस वाले को बाद में देता है। ऐसा नजारा अवंतिका चौराहे पर ट्रैफिक की निगरानी में तैनात ट्रैफिक पुलिस का गैरजिम्मेदार स्टाफ उगाही करते देखा जा सकता है। बसों के लिए सडक पर पीली लाइन कहने को खींच दी है। पर सभी बसें मजबूरी में सडक के बीच चलती है। वजह साफ है बसों के लिए छोडी गई पीली लाइन पर कार पार्किंग से लेकर रेहडी-पटरी वालों का कब्जा है। ट्रैफिक रफ्तार की बजाए रेंग कर चल रहा है।इसकी किस को प्रवाह? अपना काम बनता भाड में जाए जनता की अलख उठाए वसूली जारी है। ऐसे में ये समझ नहीं आता कि सडक सुरक्षा के लिए आम जनता को या ट्रैफिक पुलिस को जागरूक किया जाए? बहरहाल दैनिक परिवहन विशेष अखबार की सडक सुरक्षा मुहिम के लिए तमाम यातायात से पीडित नागरिक आपकी मुहीम साथ -साथ है।

संस्कारशाला : प्रधानमंत्री संग्रहालय, नई दिल्ली में एक प्रेरणादायक यात्रा

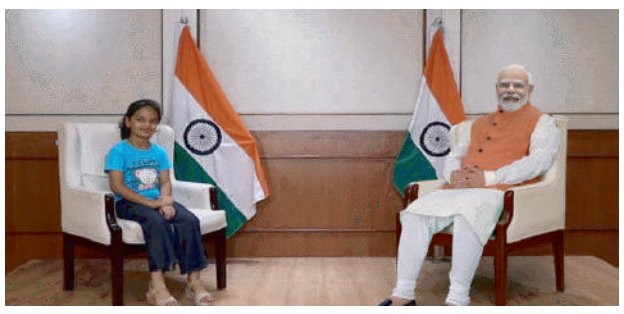

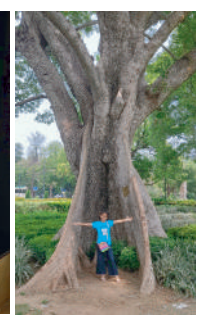

अंकुर शरण

प्रधानमंत्री संग्रहालय, नई दिल्ली एक ऐसा स्थान है जो हमारे राष्ट्र के महान प्रधानमंत्रियों की जीवन गाथा और योगदान को प्रदर्शित करता है। यह संग्रहालय हर भारतीय के लिए गर्व का स्थान है और विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए यह एक प्रेरणादायक स्थल है। अपने परिवार के साथ इस संग्रहालय की यात्रा न केवल एक शैक्षिक अनुभव है, बल्कि यह हमारी जड़ों से जुड़ने और हमारे महान नेताओं से सीखने का भी एक सुनहरा अवसर है।

हाल ही में मेरी बेटी, आद्या शरण के जन्मदिन (14 जुलाई) के अवसर पर हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय की यात्रा की। इस यात्रा ने हमें अपने महान प्रधानमंत्रियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को नजदीक से देखने और समझने का मौका दिया। संग्रहालय में प्रदर्शित वस्त्र, तस्वीरें, और अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं हमें यह समझाने में सफल रहीं कि हमारे नेताओं ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया और किस प्रकार उन्होंने हमारे राष्ट्र को आज की स्थिति तक पहुँचाया।

आद्या के और मेरे पसंदीदा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचवाना, उनके हस्ताक्षर किए हुए पत्र को सहेज कर रखना और उनके साथ एक वॉक का अनुभव एक सपने से कम नहीं था। 'मन की बात' सुनते-सुनते यह सपना साकार हुआ, और अब हम आशा करते हैं कि हमारा दूसरा सपना भी पूरा हो, जिससे हम अपने मोदी जी से व्यक्तिगत रूप से मिल सकें।

आद्या के साथ यह यात्रा न केवल हमारे लिए एक यादगार अनुभव था, बल्कि यह एक सजीव उदाहरण भी है कि कैसे हमें अपने बच्चों को हमारी समृद्ध धरोहर से जोड़ना चाहिए।

बच्चों और युवाओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे अपने अवकाश के समय को शॉपिंग मॉल्स में बिताने के बजाय ऐसे स्थानों पर जाएं जहां वे अपने देश के महान नेताओं के बारे में जान सकें। यह न केवल उनके ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की भावना भी विकसित करता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एक ऐसी ही जगह है जहां बच्चे और युवा अपने इतिहास से रूबरू हो सकते हैं और अपने आदर्शों को जान सकते हैं।

इस यात्रा ने हमें यह महसूस कराया कि हमें अपने जीवन में ऐसे स्थानों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए जो हमारे ज्ञान को समृद्ध करें और हमारे बच्चों को सही दिशा में प्रेरित करें। प्रधानमंत्री संग्रहालय एक ऐसा ही स्थान है, जो हर भारतीय परिवार को अवश्य देखना चाहिए। यह यात्रा हमारे लिए एक संस्कारशाला की तरह थी, जहां हमने न केवल अपने नेताओं के बारे में जाना, बल्कि उनके मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया।

आइए, हम सभी अपने बच्चों को शॉपिंग मॉल्स के बजाय ऐसे प्रेरणादायक स्थलों की यात्रा कराएं, ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़ सकें और हमारे महान नेताओं से सीख सकें। प्रधानमंत्री संग्रहालय, नई दिल्ली एक ऐसा ही स्थल है जो हमारे देश की महान धरोहर और हमारे नेताओं के अद्वितीय योगदान का साक्षी है।

प्रधानमंत्री संग्रहालय परिसर की हरी-भरी सुंदरता:

प्रधानमंत्री संग्रहालय, नई दिल्ली में कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान खींचती है, वह है यहां की मनमोहक हरियाली। इस संग्रहालय का परिसर हरे-भरे वृक्षों और सुंदर बाग-बगीचों से सजा हुआ है, जो न केवल इसे एक ऐतिहासिक स्थल बनाते हैं, बल्कि इसे प्राकृतिक सुंदरता का भी अद्वितीय उदाहरण बनाते हैं। संग्रहालय परिसर में घूमते हुए, हमने कई विशाल वृक्षों को देखा, जिनकी ऊंचाई और फैलाव वाकई चकित करने वाले थे। ये पेड़ सिर्फ अपने आकार के कारण ही नहीं, बल्कि उनकी उम्र और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी अद्वितीय थे। इनमें से कुछ पेड़ तो इतने पुराने थे कि उन्होंने शायद कई ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी शाखाओं से गुजरते देखा होगा। इन वृक्षों की छांव में बैठकर इतिहास की बातें सुनना और उन्हें महसूस करना एक अलग ही अनुभव था।

यहाँ की हरियाली केवल मन को शांति ही नहीं देती, बल्कि यह हमें प्रकृति से जुड़ने और उसकी सुंदरता का आनंद लेने का मौका भी देती है। परिसर में लगे फूलों की क्यारियां और सुंदर घास के मैदान इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। चलते-चलते हमने यहां के कई पौधों और वृक्षों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, जो हमें पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी समझाते हैं।

यह संग्रहालय केवल इतिहास प्रेमियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग है। यहाँ की हरियाली और विशाल वृक्ष आपको एक अद्भुत शांति और सुकून का एहसास कराते हैं।

अगर आपने कभी किसी ऐतिहासिक स्मारक या सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान की ऐसी ही कोई यात्रा की है, तो कृपया अपने अनुभव और कहानी हमारे साथ साझा करें। हमें आपसे सुनकर बहुत खुशी होगी। चलिए, मिलकर अपने भारत की सुंदर धरोहर का आनंद लें और उसकी महिमा का प्रचार करें।

अपने अनुभव और कहानी हमें indiangreenbuddy@gmail.com पर भेजें।

प्रधानमंत्री संग्रहालय में 'आर्ट@म्यूजियम' का सुंदर आयोजन: आर्ट निर्भर भारत की ओर एक कदम

प्रधानमंत्री संग्रहालय में स्थानीय कला समुदाय द्वारा आयोजित 'आर्ट@म्यूजियम' एक बेहद सुंदर और प्रेरणादायक पहल साबित हुई। इस आयोजन में हमें स्मारिका क्षेत्र में मौके पर ही कला रचने का अद्भुत अवसर मिला। इस तरह की पहल न केवल आर्टनिर्भर भारत की अवधारणा को सशक्त बनाती है, बल्कि स्थानीय कारीगरों और कलाकारों को एक मंच भी प्रदान करती है।

इस आयोजन में कई युवा और बच्चे शामिल हुए और उन्होंने अपने कला रूपों के माध्यम से योगदान दिया। यह देखकर बहुत खुशी हुई कि युवा पीढ़ी भी कला के इस महान कार्य को समर्थन देने में आगे बढ़ रही है।

कार्यक्रम के दौरान, आद्या शरण (कुहू), जिसे 'नेस्टिंग गर्ल' के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा किए गए कार्यों को भी सराहा गया। उनकी कलाकृतियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और उनकी कला के प्रति समर्पण की प्रशंसा की गई।

आर्ट@म्यूजियम पहल को संबंधित अधिकारियों और आयोजकों द्वारा अत्यधिक सराहा गया। उन्होंने इस तरह के आयोजनों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि ये न केवल कला के प्रति लोगों में रुचि बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने में मदद करते हैं।

काबुकी दिल्ली की टीम को प्रधानमंत्री संग्रहालय में इस दो दिवसीय आयोजन के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए बधाई।

इस आयोजन ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज को जोड़ने और उसे सशक्त बनाने का एक सशक्त माध्यम भी है। आर्टनिर्भर भारत की दिशा में यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम है, और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे, जो कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

इनसाइड

फीमेल ऑर्गेज्म से जुड़े हैं ये 5 अज्ञात फैक्ट्स, जानकर आप भी हो जाएंगी हैरान

महिलाओं के शरीर से जुड़े फैक्ट्स महिलाओं को खुद पता नहीं होते हैं. उन्हें अपने शरीर के बारे में समझने की जरूरत है, खुलकर बात करने की जरूरत है, न की इस पर चुप रहने की. सेक्स जरूरी है और इससे जुड़े अंग जो आपको उत्तेजित करते हैं उसके बारे में जानना भी जरूरी है. आज हम 5 ऐसे ही अज्ञात तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होने वाली है'

महिलाओं में 3 से अधिक यौन अंग होते हैं ! महिला के बाहरी यौन अंग को लेबिया मेजोरा कहा जाता है. यह योनि के खुलने के आसपास वाली त्वचा होती है, जो 2 फोल्ड्स में मौजूद होती है. भीतरी यौन अंग को लेबिया माइनोरा कहा जाता है, जो लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होते हैं. आंतरिक महिला यौन अंग में अंडाशय (Ovaries), फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय (Uterus), गर्भाशय ग्रीवा (Cervix) और योनि (Vagina) हैं. महिला सेक्स सिर्फ प्रजनन (Reproductive) अंग नहीं हैं, वे महिलाओं में यौन उत्तेजना का भी काम करते हैं.

विभिन्न चरणों में समझे फीमेल ऑर्गेज्म जिस तरह से एक महिला को ऑर्गेज्म प्राप्त होता है वह पुरुषों की तुलना में अलग होता है. पहले एक उत्तेजना चरण होता है जो शारीरिक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होता है. दूसरा जब क्लाइटोरिस प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है. क्लाइटोरिस को "फीमेल पेनिस" भी कहते हैं, जो महिलाओं के शरीर का सबसे ज्यादा उत्तेजित करने वाला अंग माना गया है. तीसरा चरण ऑर्गेज्म से ठीक पहले होता है जहां हृदय गति सबसे अधिक होती है. अंतिम चरण रिलीज या संभोग का चरण है.

क्लाइटोरिस सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग

क्लाइटोरिस सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें 8,000 से अधिक तंत्रिका हैं. इस प्रकार से यह सबसे अधिक उत्तेजना उत्प्रेरण अंगों में से एक है. ऐसा कहा जाता है कि 75 प्रतिशत से अधिक महिलाओं में क्लाइटोरिस को छूने पर ही ऑर्गेज्म चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है. तीन-चौथाई क्लाइटोरिस छिपे हुए होते हैं शायद इसीलिए इसे कामोत्तेजना वाले अंग के रूप में नहीं देखा जा सकता है. क्लाइटोरिस का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को आनंद देना होता है.

फीमेल ऑर्गेज्म में स्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

महिलाओं में स्तन और निप्पल की उत्तेजना के कारण भी ऑर्गेज्म प्राप्त किया जा सकता है. अध्ययनों से पता चला है कि निप्पल को उत्तेजित करने से भी जेनाइटल्स यानी जननांगों को सक्रिय किया जा सकता है.

महिला को आनंद देने वाले अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं

महिलाओं को सुख देने वाले अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एक अंग से प्रत्येक अंग उत्तेजित होता है. जिस वजह से महिलाओं को अधिक आनंद की प्राप्ति होती है. पार्टनर की प्राथमिकता, पसंद और सेक्सुअल एनाटॉमी को ध्यान में रखें. इंटरकोर्स यानी संभोग के दौरान यह महत्वपूर्ण होता है.

महिलाओं में होने वाली हेल्थ से जुड़ी परेशानियां, जिनके बारे में जानना है बेहद जरूरी

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कुछ अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की संभावना अधिक रहती है लेकिन समय पर इलाज होने पर उपचार संभव है. जानिए महिलाओं में होने वाली कुछ सामान्य हेल्थ से जुड़ी परेशानियों के बारे में. क्या आप जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक डेथ्स की संभावना अधिक होती हैं. यही नहीं, डिप्रेशन और एंग्जायटी की समस्या भी महिलाओं में अधिक देखी जाती है. महिलाओं और पुरुषों दोनों कई हेल्थ कंडिशंस से गुजरते हैं लेकिन कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, जो महिलाओं में ज्यादा देखी जाती हैं. वहीं जानकारी की कमी या लापरवाही के कारण कई महिलाओं की हेल्थ कंडिशंस का समय पर निदान नहीं हो पाता.

छात्राओं का बढ़ता यौन उत्पीड़न रोकें

छात्राओं का यौन उत्पीड़न शिक्षा समाज में एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इसे राज्य सरकारें कभी भी हल्के से न लें। क्यों न हमारे पत्रकार दोस्तों और सरकारों द्वारा यह पड़ताल की जाए कि राज्यों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी व कोचिंग सेंटर्स में छात्राओं की अस्मत की सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं। कहीं पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटना होने पर शिक्षा संस्थानों पर तुरंत वाजिब एक्शन लोकहित में होना चाहिए'

डा. वरिंदर भाटिया

देश के अनेक राज्यों के शिक्षा संस्थानों मे छात्राओं का यौन शोषण चिंताजनक बनता जा रहा है। इसी संदर्भ में हाल ही में कोचिंग सेंटरों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि सभी कोचिंग संस्थानों को छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रभावी क़दम उठाने के निर्देश दिए जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग सेंटरों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि वे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 और इसके तहत दिए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से अमल सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें। आयोग ने कहा है कि हाल के सालों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन गया है। आयोग कोचिंग/शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर चिंतित है। आयोग ने सभी हितधारकों के बीच कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए भी कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम की जगह पर यौन उत्पीड़न के मामले जिम्मेदारी और प्रभावी ढंग से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि ये कोचिंग सेंटर संबंधित प्राधिकरण में पंजीकृत हों और केंद्रों को चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की गई हो। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) विधेयक 2012 (संशोधित विधेयक) संसद द्वारा 2013 में पारित किया गया था। यौन उत्पीड़न कानून संगठित और असंगठित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। हमारी जानकारी के लिए, किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी लालच देकर अनावश्यक रूप से दबाव बनाना भी यौन शोषण अपराध का हिस्सा होता है। कार्यस्थल पर अश्लील चित्र दिखाना, शरीर के यौन अंग पर टिप्पणी करना, यौन गतिविधियों की अफवाह फैलाना, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी महिला के साथ अभद्रता या गाली गलौज करना भी यौन शोषण के अंतर्गत आता है। शिक्षा के मंदिर इसका अपवाद नहीं हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं की तुरंत रिपोर्टिंग की जरूरत होती है परन्तु छात्राओं द्वारा किन्हीं कारणों से इसको न बताने पर उनका शोषण बढ़ता जाता है। बेहतर है सरकारें छात्राओं से मिली इस जानकारी को गुप्त रख छद्म जांच करें और कार्रवाई करें। कुछ समय से देश के अनेक राज्यों में छात्राओं के यौन शोषण की घटनाओं में बढ़ोतरी से सामाजिक व्याकुलता बढ़ रही है। यौन शोषण का छात्राओं के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जिस मनुष्य का यौन शोषण हुआ होता है वह पूरी मानवता से नफरत करने लगता है। उसे हर व्यक्ति केवल शोषण करने वाला ही दिखता है क्योंकि यह उसकी मानसिकता बन जाती है जिसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है और उसके लिए बहुत सी तकलीफों का सामना भी करना होता है, जैसे कि वह यौन शोषण उसे बार-बार याद आते रहते हैं और उसको और ज्यादा मानसिक तकलीफ होती है जो उसके लिए बहुत कष्टदायक होती है, यह जिस तन लागे वोही जाने वाली स्थिति होती है। आज सिर्फ कोचिंग सेंटर ही नहीं, स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कुछ समय पहले एक छात्र ऑडिट के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 24 कॉलेजों और विभागों में सर्वेक्षण किया गया। कुल 810 छात्र-छात्राओं ने सवालों के जवाब दिए। इसमें करीब 90 प्रतिशत महिलाएं और 10 प्रतिशत पुरुष थे। रिपोर्ट में कहा गया कि हर चार छात्राओं में से एक ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की। यौन उत्पीड़न के 188 मामलों में 40 मामले शारीरिक उत्पीड़न के थे। उत्पीड़न के पांच में से एक मामला जबरदस्ती छूने या पकड़ने का था। उत्पीड़न के प्रत्येक पांच मामलों में से एक सोशल मीडिया पर ट्रोल करने या कॉल या लिखित वॉट्सऐप मैसेजों के जरिए उत्पीड़न का था।

जवाब देने वाले तकरीबन 80 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने परिसर में असुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन की ओर से कदम नहीं उठाने को जिम्मेदार ठहराया। ऐसा ऑडिट सरकारों की तरफ से सभी कॉलेजों में करवाया जाना चाहिए। सच बोलें तो सिर्फ छात्राएं ही नहीं, अमूमन सभी लड़कियों की लाइफ बहुत टफ होती है। उन्हें हर कदम पर न जाने कितनी गंदी नजरों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर उन्हें खुद को सुरक्षित रखने की चिंता लगी रहती है। ऑफिस या स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, अब तो लड़कियां घर तक पर सेफ नहीं हैं। आए दिन पिता या भाई द्वारा भी रेप की खबरों से सोशल मीडिया भरा रहता है। ऐसे माहौल में आप भी समझ सकते हैं कि यौन उत्पीड़न की वजह से लड़कियों के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया है। कॉलेज की बात करें तो वहां पर भी लड़कियों को यहां तक कि तदर्थ महिला अध्यापकों को भी पक्की जॉब के लिए यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। कई प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल रहते हैं जो बेडरूम सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। यह एक न हजम होने वाली सच्चाई हो सकती है। छात्राओं के यौन शोषण को लेकर विदेश की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। ब्रिटेन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आता है लेकिन पिछले कुछ समय पहले की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यहां पर छात्राओं का यौन उत्पीड़न सबसे ज्यादा होता है। कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों का यौन उत्पीड़न किया जाना ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में महामारी के स्तर तक पहुंच चुका है। वहां की कई यूनिवर्सिटियों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कर्मचारियों को विद्यार्थियों पर यौन संबंध के लिए दबाव बनाने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, ऐसा होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी पर्याप्त नियम नहीं हैं। बस इसी बात से आप जान सकते हैं कि जब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में लड़कियों और स्टूडेंट्स का ये हाल है तो फिर बाकी कॉलेजों में स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा होगा। एक ज़माने में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को विद्या का मंदिर समझा जाता था और आज अपने देश में भी इनमें से कुछ की छवि इतनी ज्यादा धूमिल हो गई है कि अब इन्हें विद्या का मंदिर नहीं कहा जा सकता है। राज्य सरकारें ऐसे इंतजाम करें, ऐसे रिपोर्टिंग सिस्टम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कहें जिससे छात्राओं के यौन शोषण के मामले दबे नहीं।

छात्राओं का यौन उत्पीड़न शिक्षा समाज में एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इसे राज्य सरकारें कभी भी हल्के से न लें, क्यों न हमारे पत्रकार दोस्तों और सरकारों द्वारा यह पड़ताल की जाए कि राज्यों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर्स में छात्राओं की अस्मत की सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं। कहीं पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटना होने पर शिक्षा संस्थानों पर तुरंत वाजिब एक्शन लोकहित में होना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि छात्राओं की पढ़ाई-लिखाई को उत्साह देने के लिए उन्हें सुरक्षित अकादमिक माहौल दिया जा सके। छात्राओं के हॉस्टल उनके लिए कितने सुरक्षित हैं, यह वैरिफिकेशन जरूरी और तुरंत हो तो बेहतर है। छात्राओं को सुरक्षित करना ही होगा।

मां बनने के बाद छोटी-छोटी बातें भूलने लगी हैं, तो 'मॉमी ब्रेन' प्रॉब्लम से ऐसे करें बचाव

क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप मां बनने के बाद छोटी छोटी बातें भूलने लगीं हैं? कभी ऐसा हुआ हो कि आप कमरे में तेजी से गईं और वहां जाकर भूल गईं कि आप क्यों कमरे में आईं या गाड़ी की चाबी हाथ में हैं और आप पूरे फ्लैट में चाबी ढूंढती रहीं? अगर आप ऐसी समस्याओं से परेशान हो गई हैं तो यह अकेले आपकी ऐसी समस्या नहीं है. दरअसल इस समस्या को मॉमी ब्रेन के नाम से जाना जाता है. वेरीवेलफैमिली के मुताबिक एक स्टडी में पाया गया है कि बच्चे को जन्म देने से मां का मस्तिष्क भी काफी प्रभावित होता है और कभी-कभी लंबे समय तक इसका असर कायम रहता है. ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने भी ये पाया गया है कि मां बनने से महिला के याददाश्त क्षमता पर खराब असर पड़ता है.

क्या है इस परेशानी की वजह?

कई शोधकर्ताओं ने माना कि ये परिवर्तन एक नई मां को अपने बच्चे की देखभाल करने की क्षमता को बढ़ाने का एक नेचुरल तरीका होता है. यह भी कहा जा सकता है कि मस्तिष्क में ये परिवर्तन दरअसल नई माताओं को बच्चे की जरूरतों को अपनाने और उन्हें पूरा करने के लिए अहम होता है.

मॉमी ब्रेन से उबरने के उपाय

धैर्य रखें- शरीर में हुए इस बायोलॉजिकल बदलाव की वजह से आप खुद से परेशान हैं और इरिटेट हो जाती हैं आपको बता दें कि अगर आप थोड़ा धैर्य रखें और किसी भी काम को पूरा करने के लिए थोड़ा एक्ट्रा प्लान बनाएं तो मॉमी ब्रेन की समस्या से उबर सकती हैं.

लिस्ट बनाएं- इस समस्या से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने हर काम की लिस्ट बनाएं. इसके लिए आप एक नोटबुक कैरी करें और जब भी कुछ याद आए तो उसे लिख लें. ऐसा करने से आप जरूरी चीजों को भूलेंगी नहीं.

प्लान बनाएं- आप पहले से चीजों के लिए प्लान बनाएं और अपनी हर चीज को सही जगह पर रखने की आदत डाल लें. इससे आपका काम काफी आसान बन जाएगा. मसलन, आप अगर सुबह डॉक्टर के पास जाने वाली हैं तो रात में ही सारा सामान तैयार रखें. आप चाभी, वॉलेट आदि हमेशा एक ही जगह पर रखें आदि.

पर्याप्त नींद जरूरी- नई मांओं की व्यस्तता 24 घंटे की होती है. लेकिन आपको कुछ इस तरह अपने रुटीन को फॉलो करना है कि आपकी नींद पूरी हो सके. इसके लिए आप परिवार के लोगों की मदद ले सकती हैं और बच्चे के साथ ही सोने और जागने की रुटीन को फॉलो कर सकती हैं. भरपूर नींद आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा और ये बेहतर तरीके से काम कर पाएगा.

ब्रेन को दें एक्स्ट्रा केयर- ब्रेन के लिए आप अपने खानपान पर ध्यान दें और ब्रेन गेम खेलें. ब्रेन गेम आपके दिमाग को एक्टिव रखने का काम करेगा और ये बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे. इसके अलावा, आप उन चीजों को डाइट में शामिल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो और भरपूर प्रोटीन हो.

शादी के बाद महिलाओं के लिए करियर का चुनाव : विजय गर्ग

शादी के बाद एक महिला के लिए प्रोफेशन चुनना एक अहम फैसला होता है, जो उसके जीवन में काफी बदलाव ला सकता है। शिक्षित और कम शिक्षित दोनों महिलाओं के लिए, यह विकल्प व्यक्तिगत कौशल, झुकाव और जीवन की स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। हालाँकि, कुछ पेशे दोनों प्रकार की महिलाओं के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इस लेख में हम दोनों प्रकार की महिलाओं के लिए कुछ उपयुक्त व्यवसायों पर चर्चा करेंगे। शिक्षित महिला के लिए व्यवसाय: शिक्षक - शिक्षक का व्यवसायशिक्षित महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक एवं उपयोगी विकल्प। इस कार्य में महिलाओं को स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का अवसर मिलता है, जिससे स्थिर रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। शिक्षक के रूप में महिलाएँ छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाती हैं और उन्हें सफलता की मंजिल तक पहुँचने में मदद करती हैं, जिससे शिक्षकों को छात्रों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की संतुष्टि मिलती है। एक शिक्षक का शेड्यूल अधिकतर निश्चित होता है। जो परिवार के साथ हैखर्च करना सुविधाजनक है. छुट्टियों के प्रावधान के कारण पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। इस प्रकार, शिक्षित महिलाओं के लिए शिक्षक का पेशा एक उचित और समझदार विकल्प है, जो न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार करता है बल्कि समाज में सम्मान और सम्मान भी देता है। डॉक्टर - मेडिकल पेशा साक्षर महिलाओं के लिए भी उपयुक्त है, खासकर यदि वह मेडिकल क्षेत्र में रुचि रखती हो। डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत और पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित पेशा है। औरतस्त्री रोग, बाल रोग और अन्य क्षेत्रों के लिए पाया जा सकता है। इंजीनियर - शिक्षित महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग भी एक अच्छा विकल्प है। इंजीनियरिंग के कई क्षेत्र हैं, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस आदि। महिलाओं को इन क्षेत्रों में करियर के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। वकील- शिक्षित महिलाओं के लिए भी वकील बनने के बहुत अच्छे अवसर हैं। कानून और न्याय के क्षेत्र में महिलाएं वकील या जज भी बन सकती हैं। यह क्षेत्र नैतिकता और सच्चाई के लिए जाना जाता है, जिससे समाज में मान-सम्मान मिलता है. एमबीए प्रोफेशन - एमबीए करने के बाद महिलाएं बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग आदि में काम कर सकती हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में उच्च पदों तक पहुंचने के लिए यह एक अच्छा पेशा है। कम पढ़ी-लिखी महिलाओं के लिए सिलाई-कढ़ाई का पेशा - कम पढ़ी-लिखी महिलाओं के लिए सिलाई-कढ़ाई का काम एक अच्छा विकल्प है। वे यह काम घर से ही कर सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान दे सकते हैं। गृह उद्योग - गृह उद्योग, जैसे कागज के पैकेट, खिलौने बनाना, अचार बनाना, उपकरण बनाना आदि कमशिक्षा महिलाओं को बेहतर अवसर प्रदान कर सकती है।

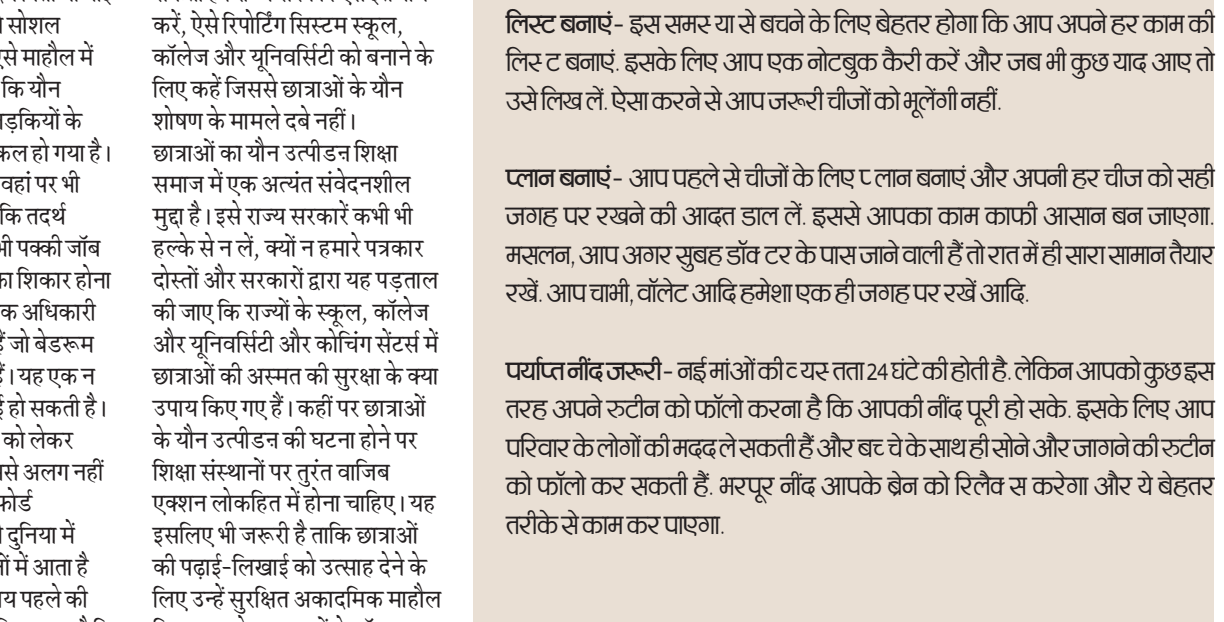

वे यह काम घर बैठे भी कर सकते हैं. ब्यूटीशियन- कम पढ़ी-लिखी महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर का काम भी एक अच्छा विकल्प है। सौंदर्य सेवा हमेशा मांग में रहती है, जो इन महिलाओं के लिए आय का एक अच्छा स्रोत हो सकती है। कुंच सेवा - शादी के बाद कम पढ़ी-लिखी महिलाएं कुंच सेवा चलाकर अपने घर को आय का जरिया बना सकती हैं। बच्चों की देखभाल के लिए यह एक अच्छा पेशा है। फील्ड वर्क - जैसे खेती, डेयरी, पोल्ट्री फार्म आदि में काम करना कम पढ़ी-लिखी महिलाएंआपको आय का कोई स्रोत मिल सकता है। ये नौकरियां उनके जीवन को बेहतर बना सकती हैं और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। शादी के बाद पेशा चुनते समय महिलाओं को अपने झुकाव, कौशल और जीवन की स्थिति पर विचार करना चाहिए। कुछ पेशे जैसे शिक्षक, डॉक्टर, सिलाई, कढ़ाई, सौंदर्य सेवा आदि शिक्षित और कम शिक्षित महिलाओं दोनों के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। प्रत्येक महिला को अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही पेशे का चयन करना चाहिए। इस लेख में दिया गया हैपिछले व्यवसायों के ज्ञान के साथ, हमने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि हर महिला अपने लिए सही और सफल पेशा चुन सके।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य
शैक्षिक स्तंभकार मलोट

सुकेश की रोल्स रॉयस, फेरारी और रेंज रोवर सहित 26 लग्जरी कारें होंगी नीलाम, कोर्ट ने कहा- नहीं तो खराब हो जाएंगे वाहन

परिवहन विशेष। एसडी सेठी

सुकेश चंद्रशेखर की लग्जरी कारें नीलाम की जाएंगी। इन कारों की संख्या 26 है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसकी अनुमति दे दी है। लग्जरी कारों में रोल्य रॉय घोस्ट फेरारी और रेंज रोवर शामिल है। कोर्ट ने कहा कि इन कारों को गोदाम में नहीं रखा जा सकता है एक समय के बाद यह खुद खराब हो जाएंगी। सुकेश की पत्नी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

नई दिल्ली। 200 करोड़ की ठगी करने के आरोपी ठग सुकेश चंद्रशेखर की अपराध की आय से खरीदी गई 26 हाई-एंड लग्जरी कारों की नीलामी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कारों को बेचने की ईडी को अनुमति देने के निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा है।

अदालत ने माना कि एक समय के बाद वाहन स्वाभाविक रूप से समय के साथ खराब हो जाएंगे। ऐसे में ईडी को निर्देश दिया जाता है कि इन कारों की बिक्री से उत्पन्न पूरी राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने का निर्देश दिया।

गोदाम में रखे रहने से वाहन हो जाएंगे खराब

चंद्रशेखर की पत्नी लीना पालोज की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि वाहन को लंबे समय तक कंटेनर गोदाम में रखने से वह खराब हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी कार को वर्षों तक खड़ा छोड़ दिया जाए तो जंग जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। इसके कारण महंगी कारों को गंभीर रूप से नुकसान हो सकता है।

रोल्स रॉयस, फेरारी सहित 26 लग्जरी कारें

अदालत ने कहा कि इन महंगी 26 लग्जरी कारों में रोल्स रॉयस, फेरारी, रेंज रोवर आदि शामिल हैं और इनका रख-रखाव भी महंगा है। निचली अदालत ने ईडी को कानून के अनुसार कारों को बेचने की अनुमति दी थी और कहा था कि दिल्ली पुलिस या आर्थिक अपराध शाखा का एक प्रतिनिधि भी उन वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है।

निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए पीठ ने कहा कि आटोमोबाइल उद्योग में वाहनों का दाम कम होना भी एक घटक है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रासंगिक नियम जब्त किए गए वाहनों की बिक्री की अनुमति देते हैं।

जेल में बंद रहने से कारों के नंबर याद नहीं

पालोज ने तर्क दिया था कि 16 महीने से अधिक समय तक जेल में अलग-थलग रहने के बाद वह अवसाद से पीड़ित थी और उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। ऐसे में वह केवल दो कारों, रोल्स रॉयस घोस्ट और ब्रेबस के पंजीकरण नंबर याद रखने में सक्षम थी।

अपराध की आय के दायरे में नहीं ये कारें

उन्होंने कहा कि ये दोनों कारें 2018 में खरीदी गई थीं, जोकि अपराध के आय से बहुत पहले की थी। उन्होंने दावा किया कि उक्त कारें अपराध की आय के दायरे में नहीं आ सकती हैं। यह भी दावा किया केवल चंद्रशेखर की पत्नी होने के कारण उन्हें मामले में फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया कि उनका कार खरीदने और बेचने का स्वतंत्र व्यवसाय था और अधिकांश कारें कानूनी रूप से वैध ऋण समझौतों पर ली गई हैं।

वहीं, ईडी ने तर्क दिया था कि याचिका निरर्थक हो चुकी है क्योंकि ट्रायल कोर्ट के वर्ष 2022 और 2023 के दो आदेशों के मद्देनजर उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद 26 में से 17 कारों की नीलामी पहले ही की जा चुकी है।

पालोज के तर्कों पर कोर्ट ने उठाए सवाल

अदालत ने पालोज के दो अलग-अलग तर्कों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ तो एक सांस में उन्होंने दावा किया कि अवसाद के कारण उन्हें कारों के विवरण याद नहीं हैं। वहीं, दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा अधिकांश कारें कानूनी रूप से वैध ऋण समझौतों के आधार पर ऋण पर ली गई थीं।

कारों के दस्तावेज और होंगे विवरण

एक समझदार इंसान जो 26 शानदार कारें खरीदने में सक्षम है, उसके पास न केवल अपनी आय के दस्तावेज और विवरण होंगे, बल्कि ऐसी लक्जरी कारों की खरीद/रखरखाव पर किए गए खर्च के सभी विवरण भी होंगे। हालांकि, पालोज ने इस संबंध में अदालत के समक्ष कोई दस्तावेज नहीं रखा है।

दिल्ली पुलिस ने पहले रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह के पति/पत्नी से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी की थी। इसके अलावा भी चंद्रशेखर के विरुद्ध देशभर में कई मामलों में जांच चल रही है।

दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी के. कविता की बिगड़ी तबीयत, तिहाड़ से लाकर अस्पताल में कराया भर्ती

दिल्ली शराब घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई द्वारा आरोपी बनाई गई बीआरएस की नेता के कविता की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उपलब्ध कराई है। के. कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा आरोपी बनाई गई बीआरएस नेता के. कविता की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यह जानकारी तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उपलब्ध कराई है। के. कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में के. कविता जेल संख्या-6 में बंद हैं।

तेज बुखार की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती

बीआरएस नेता को तेज बुखार की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।

सबसे पहले सीबीआई ने कसा था के. कविता पर शिकंजा

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को सीबीआई ने अप्रैल में तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें इसी से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद रखा गया था। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। कविता फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों दिया आखिरी मौका, आम आदमी पार्टी से जुड़ा है मामला

परिवहन विशेष। एसडी सेठी

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई की। जिसमें कहा गया है कि वह राष्ट्रीय पार्टी बन गई है लेकिन उसे अभी तक कार्यालय के लिए जमीन मुहैया नहीं कराई गई है। पार्टी जमीन के लिए हाईकोर्ट पहुंची है। जहां अभी पार्टी का कार्यालय है उसे खाली करने का कोर्ट से निर्देश मिल चुका है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण आम आदमी पार्टी (AAP) को कार्यालय भूमि आवंटित करने पर निर्णय लेने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया। पांच जून को हाईकोर्ट ने इस मामले में आप के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को छह सप्ताह का समय दिया था।

सुनवाई के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने अदालत से चार सप्ताह का और समय देने का अनुरोध किया। निदेशालय ने कहा कि वह नवनिर्वाचित सांसदों को आवास आवंटित करने के कार्य में व्यस्त है।

ऑफिस खाली करने का अंतिम समय 10 अगस्त

वहीं, संपदा निदेशालय ने तर्क का विरोध करते हुए आप ने इस बात पर जोर दिया कि बुधवार को समाप्त हो रही छह सप्ताह की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को राउज एवेन्यू में अपना वर्तमान कार्यालय खाली करने के अंतिम अवसर के रूप में 10 अगस्त तक का समय दिया है।

मार्च माह में सुप्रीम कोर्ट ने आप को 15 जून तक राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय खाली करने का समय दिया था। शीर्ष अदालत ने नोट किया था कि यह जमीन न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित की गई थी।

आम आदमी पार्टी ने क्या कहा

आप ने कहा कि बिना किसी उपाय के पार्टी कार्यालय छोड़ने के लिए समय विस्तार की मांग की जा रही है और केंद्र ने शीर्ष अदालत के समक्ष कार्यालय स्थान के आवंटन के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करने में असमर्थता व्यक्त नहीं की है। साथ ही यह भी सवाल किया कि आखिर में अदालत आने का उद्देश्य क्या है? यदि केंद्र सरकार भूमि देना चाहती है तो उन्हें ऐसा करने से कौन रोक रहा है।

पीठ ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि कार्यालय स्थान आवंटन मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए निदेशालय को पर्याप्त समय दिया गया है और चार सप्ताह का और विस्तार नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, पीठ ने मामले के समग्र तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय अवधि 25 जुलाई तक बढ़ा दी।

साथ ही स्पष्ट किया कि अदालत उम्मीद करती है कि केंद्र सरकार आवेदक द्वारा विस्तार की मांग के लिए कोई और आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। पांच जून को सुनाए अपने निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा था कि आप अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की तरह दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने की हकदार है और केंद्र से छह सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने को कहा था।

दिल्ली में इस बार कांवड़ यात्रा में साउंड सिस्टम लगाना होगा महंगा, जानिए क्या है वजह

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में इस बार कांवड़ यात्रा में साउंड बजाना महंगा सौदा हो सकता है। सावन का महीना आने वाला है और इस दौरान शिव भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं। वह गंगाजल लेने जाते हैं। कांवड़ यात्रा में शिव भक्त काफी धूमधाम से जाते हैं। इस दौरान साउंड सिस्टम के साथ भजनों की धुन पर नाचते-गाते हैं।

नईदिल्ली। इस बार कांवड़ यात्रा में साउंड सिस्टम का इस्तेमाल महंगा सौदा हो रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार साउंड सिस्टम वालों ने किराए में 30 से 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। ऐसे में बड़ी कांवड़ में झांकियों समेत साउंड सिस्टम का औसत किराया डेढ़ से दो लाख रुपये तक का बैठ रहा है।

दिल्ली से प्रत्येक वर्ष करीब 5,000 कांवड़ झांकियां निकलती हैं, जिसमें छोटी से लेकर बड़ी झांकियां होती हैं, जो तीन दिन से लेकर 15 दिन तक के लिए होती हैं। इस वर्ष झांकियों में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का अनुमान है। ऑल इंडिया साउंड एंड लाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर के अनुसार, महंगाई के मद्देनजर साउंड सिस्टम के किराए में बढ़ोत्तरी की गई है।

चार दिन से 15 दिनों की होती है यात्रा

सावन में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। शिवभक्त भोले बाबा को मनाने के लिए गंगा जल लाकर शिवलिंग पर आस्थापूर्वक चढ़ाते हैं। यह पूरी यात्रा काफी कठिन मानी जाती है, क्योंकि यह नंगे पैर होती है। इस यात्रा को लेकर शिवभक्तों की आस्था देखते ही बनती है।

इस वर्ष भी 15 दिन पहले से यात्रा को लेकर शिवभक्तों की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। जो शिवभक्त उत्तराखंड के गोमुख से पवित्र जल को कांवड़ में लाने जा रहे हैं, वह उसके लिए रवाना भी हो चुके हैं।

कांवड़ की सादगी से लेकर झांकियों की भव्यता

कुछ कांवड़िये कांवड़ के साथ साउंड सिस्टम लेकर चलते हैं तो अधिकांश केवल कांवड़ लेकर समूह में निकलते हैं। जबकि, कई टोलियों में साउंड सिस्टम के साथ झांकियां भी होती है। कुछ कांवड़ की भव्यता देखते ही बनती है। जो देवी-देवताओं की मूर्तियों के साथ पहाड़ बनाकर अलग वाहन में झांकियां लेकर निकलती है। उनका किराया चार से पांच लाख रुपये तक बैठता है।

ध्वनि को लेकर जारी किया गया है परामर्श

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर साउंड सिस्टम के लिए उच्चतम ध्वनि स्तर 75 डेसिबल तय की है। ऐसे में आल इंडिया साउंड एंड लाइट एसोसिएशन ने इसके लिए देशभर के साउंड सिस्टम संचालकों के लिए परामर्श पत्र जारी किया है जिसमें उसने कांवड़ के साथ चल रहे साउंड सिस्टम के लिए इस मानक के पालन का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड पुलिस प्रशासन से भी इस मामले में कार्रवाई की जगह जागरूक करने का आग्रह किया गया है।

नहीं होता ध्वनि स्तर मानक का पालन

एक साउंड सिस्टम संचालक ने बताया कि निर्धारित मानक 75 डेसिबल का पालन कठिन होता है, क्योंकि सड़क के शोर के साथ कई साउंड सिस्टम साथ चल रहे होते हैं। भक्तिभाव में उत्साह व जोश इतना होता है कि भक्तों को अंदाजा नहीं होता है कि साउंड की आवाज कितनी पहुंच गई है।

यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज

कांवड़ यात्रा को सुचारू व विघ्न रहित करने के लिए प्रशासनिक तैयारी भी तेज हो गई है। उत्तर पूर्वी जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुबोध गोस्वामी ने बताया कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ समितियों के साथ बैठक चल रही है। समितियों से कहा गया है वह अपने वालंटियर रखे और उन्हें कार्ड और एक ड्रेस दें। ताकि पता रहे कि वह वालंटियर है।

कैंप में जिस जगह प्रसाद बनेगा वहां पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं। आग बुझाने के यंत्र शिविर में होने चाहिए। जो वालंटियर हो वह डाक कांवड़ को ठीक जगह खड़ा करवाए और बाकी वाहनों को पार्किंग में लगवाए। सुप्रीम कोर्ट ने डाक कांवड़ की आवाज निर्धारित की हुई है, उसका पालन सुनिश्चित किया जाए।

2024-लोकसभा चुनाव हारे 200 सांसदो को सरकारी बंगले खाली करने के थमाए नोटिस

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। सरकारी बंगलों पर 2024 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद कब्जा जमाए बैठे 200 सांसदों को घर से बाहर खदेड़ने के तहत उन्हें बंगला खाली करने के नोटिस थमा दिए है। सूत्रों के मुताबिक लुटियंस दिल्ली में आवंटित सरकारी बंगलों को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने सोमवार को सभी पूर्व सांसदो को सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जाधारियों से बेदखली) अधिनियम के तहत ये नोटिस जारी किए गए है। बता दें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलो के मंत्रालय के नियमों के मुताबिक पूर्व सांसदों को 17वीं पिछली लोकसभा भंग होने के एक महीने के भीतर अपने सरकारी बंगले खाली करने होते हैं।लेकिन बडी संख्या में पूर्व सांसद की जगह नए चुनकर आने के बावजूद किसी न किसी बहाने बंगले पर कब्जा बरकरार रखने की जुगाड में रहते है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 200 से अधिक पूर्व सांसदो को निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने के कारण ही नोटिस थमाया गया है। सूत्रों के मुताबिक यदि वे शीघ्र ही अपने सरकारी आवास खाली नहीं करते तो अधिकारियो की टीम शीघ्र ही बलपूर्वक बेदखली के लिए 'फोर्स के साथ भेजी जाएगी। बता दें किलोकसभा सचिवालय सांसदो को आवास उपलब्ध कराता है, वहीं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, (एचयूए) केंद्रीय मंत्रयो को लुटियंस दिल्ली में बंगले करता है।

दरअसल 18वीं लोकसभा में जीत कर आए नए सांसद इन्हीं कब्जाधारियों की वजह से उन्हें मंत्रालय आवास मुहैया नहीं करवा पाई है। फिलहाल बीजेपी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी, डॉ.महेंद्र नाथ पांडे ने अपना बंगला खाली कर दिया। वहीं सांसद व शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर को लोधी रोड का बंगला आवंटित कर दिया गया है।

रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, ये मांगें पूरी होने का मिला आश्वासन; पढ़ें- कब से शुरू होंगी इमरजेंसी सेवाएं

जीटीबी अस्पताल में आखिरकार रेजिडेंट डॉक्टरों व नर्सिंग कर्मचारियों की की हड़ताल खत्म हो गई है। दिल्ली सरकार के विशेष स्वास्थ्य सचिव डॉक्टरों के बीच पहुंचे और उनके साथ बैठक की। बैठक में डॉक्टरों की मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया जिसके बाद हड़ताल खत्म हो गई। अस्पताल में मरीज की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। पढ़िए अस्पताल में कब से इमरजेंसी सेवाएं शुरू होंगी।

नई दिल्ली। दिल्ली के नामी जीटीबी अस्पताल में हुई गोलीबारी के विरोध में मंगलवार को भी डॉक्टरों हड़ताल जारी रही। इसी बीच दिल्ली सरकार के विशेष स्वास्थ्य सचिव दानिश अशरफ व अस्पताल प्रशासन के साथ हुई बैठक में मांगों का आश्वासन मिलने के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों व नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है।

बैठक में क्या-क्या हुआ

बैठक में डॉक्टरों की मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया। तीमारदारों का कार्ड बनाने को लेकर सख्ती, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, इमरजेंसी क्षेत्रों में हथियार वाले सुरक्षा गार्ड, पुलिस की पेट्रोलिंग, जीटीबी की चिकित्सा निदेशक का प्रतिदिन पूरे अस्पताल में दौरा, प्रत्येक विभाग के प्रभारी का दौरा समेत सभी मांगों का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल को खत्म कर दिया गया है।

बताया गया कि बुधवार को मोहर्रम की छुट्टी रहेगी। गुरुवार से सामान्य दिनों की तरह ओपीडी व वार्ड और सर्जरी ओटी में उपचार शुरू हो जाएगा। यह भी बताया गया कि कल यानी बुधवार को छुट्टी के दिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी।

ये थीं डॉक्टरों की मांगें

1. सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सुरक्षा प्रणालियां।

2. प्रवेश बिंदुओं पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र गार्ड।

3. सभी प्रवेश बिंदुओं पर मेटल डिटेक्टर गेट और सभी प्रवेश द्वारों पर हाथ से पकड़े जाने वाले मेटल डिटेक्टर उपकरण।

4. अस्पताल परिसर में कानून एवं व्यवस्था का समुचित कार्य सुनिश्चित करना।

5. वॉकी-टॉकी सहित उचित संचार उपकरणों के साथ त्वरित प्रतिक्रिया के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में बाउंसरों के साथ उचित सुरक्षा टीमों की तैनाती। (प्रत्येक वार्ड में कम से कम 2 गार्ड)

6. सुरक्षा संबंधी आपात स्थिति के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन जो किसी भी शिकायत और मुद्दे पर कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है (24*7)।

7. रैपिड रिस्पांस टीम में प्रभारी कांस्टेबल, SHO GTB एन्क्लेव, MOIC सुरक्षा, सुरक्षा पर्यवेक्षक/मालिक और MD GTBH शामिल हैं।

8. सभी संवेदनशील क्षेत्रों में उचित आपातकालीन निकास प्रणाली।

लापरवाही की लत : विजय गर्ग

आज के हमारे सामान्य जीवन में सब कुछ बस यों ही चलता जा रहा है। चाहे हम घर पर हों या बाहर हों, हम सबका जीवन बदस्तूर जारी है। बात सिर्फ इतनी-सी है कि हमने बस यों ही जीवन जीने की कला सीख ली है। हमारा पूरा जीवन 'चलता है सब' के आधार पर चल रहा है। हमारे दादा परदादा ने चाहे जैसे भी जिंदगी जी हो, चाहे अपने जीवन में कितने ही नियम-कायदे रखे हों, लेकिन हमारे जीवन में आज कोई नियम - कायदा नहीं है और हम 'चलता है सब' के आधार पर सिर्फ अपने आप को बनाए रखने की कोशिश में लगे रहते हैं ।

बस के ड्राइवर से लेकर दफ्तर के बाबू तक के बीच यह बात अंदर तक बैठ गई है कि हमें बस चलताऊ काम करना है और काम के प्रति ज्यादा गंभीरता हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह की प्रवृत्ति हमें अपने देश के राजनेताओं में भी नजर आती है । उनके पास भी अगर कोई व्यक्ति अपनी छोटी समस्या लेकर जाता है, तो उनका भी यही जवाब होता है कि आज सब चलता है। चाहे हम कहीं भी किसी भी चीज से जुड़े हों, हमारी प्रकृति में किसी भी काम को हल्के रूप में लेने की सोच जारी है।

इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन एक मूल वजह यह हो सकती है कि हम सब लापरवाही के शिकार हैं और यही लापरवाही हमें मूल्य विघटन की ओर लेती जा रही है । मूल्य विघटन कोई मामूली बात नहीं है, फिर भी उसको सतही तौर पर लेने की हमारी एक आदत बनती जा रही है । ऐसा क्यों न हो कि हम सब बातों को ऊपरी तौर पर लेना बंद कर दें और उनकी गहराई तक पहुंचें ? समाज में अगर किसान मरता है तो कोई बात नहीं, राजनेता घोटाला करता है तो कोई बात नहीं, भाई अपने भाई को मारता है तो चलता है, गरीब और गरीब होता है तो चलता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है तो चलता है आदि। ऐसा क्यों नहीं है कि हम सब अपनी गलती को स्वीकार करें और सही रास्ते पर चलें ? शायद ऐसा इसलिए है कि हम सभी लोग जीवन को एक यों ही चलने वाली अवस्था मानकर चलते हैं ।

काश ऐसा होता कि हम अपने जीवन को इतना हल्के तौर पर न लेते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। यहां अपने लोगों को दोषी ठहराने का इरादा नहीं है, लेकिन क्या हमने कभी देखा कि मेहनती लोग किस तरह से छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने आप को मुसीबतों से बाहर निकाल लेते हैं ? अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ? फर्क सिर्फ नजरिए का है। अगर हम चाहें तो पूरी दुनिया बदल सकते हैं।

जीवन सरलता और सहजता दोनों का नाम है, लेकिन यही सहजता कभी-कभी हमें वह नहीं सोचने देती जो हमें वाकई सोचना चाहिए। अपने पूरे जीवन का आकलन करते हुए सोचना चाहिए कि जब भी हमने किसी विषय पर गंभीरता से विचार और उस पर अमल किया है तो हमने कितनी उन्नति की है। चाहे वह हमारे स्कूल बोर्ड की परीक्षा हो या फिर नौकरी से जुड़ी कोई बात, जब-जब हमने इस 'चलता है सब' को त्यागा है, तब-तब हमने सफलता और एक कदम बढ़ाया है।

सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता को नहीं कहते, सफलता हमारी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों को भी समेटने की ताकत रखती है और सफलता के पीछे कैसी सोच होनी चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं । 'चलता है सब' के दोहरे मापदंड के साथ हम कभी भी अपनी पूर्ण सफलता का स्वाद नहीं चख सकते हैं, चाहे वह हमारा अपना जीवन हो या सार्वजनिक जीवन हो । कोशिश यह हो कि आज से और अभी से ही 'चलता है सब' के सतही जीवन को त्याग दिया जाए और अलग दौर की शुरुआत की जाए। जीवन को सकारात्मक परिवर्तन की ओर ले जाया जाए। इस तरह से हम अपने समाज को एक गंभीर चिंतन देने में सफल हो पाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक विशाल, लेकिन विविधता से भरा देश है। जिसकी अपनी समस्याएं हैं। ऐसे में अगर हम लोग प्रत्येक काम को अच्छे से करें और ध्यान रखें कि किसी काम में कोई लापरवाही न बरती जाए तो हम कहीं न कहीं देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर जा सकते हैं ।

सड़क सुरक्षा का पालन करना हमें असामयिक दुर्घटनाओं से बचा सकता है, राजनेताओं पर पैनी दृष्टि रखने से वे लोग भ्रष्टाचार के रास्ते को भूल सकते हैं, नकल रोकने पर कई लोगों का भविष्य बन सकता है, सड़कों का ध्यान रखने से देश की सड़कें गड्ढा बनने से बच सकती हैं, प्रशासन को लापरवाही से बचाया जा सकता है। साथ ही हमारे व्यक्तिगत जीवन की उन्नति संभव हो सकती है । बात सिर्फ इतनी है कि चलता है किसी भी काम के प्रति हल्के नजरिए से इतर उसे गंभीरता से लिया जाए। अगर इतना भी कर लिया जाए तो आधी मुसीबत से बाहर निकलने में काफी मदद मिल सकती है। जीवन को खूबसूरती के साथ जीना एक मूल्य होना चाहिए, बस यह याद रखा जाए कि जीवन की गंभीर बातों को गंभीरता से लेकर अपना और राष्ट्र का उत्थान करने का साहस अपने अंदर कायम रखा जाए । अगर इतना काम हमने कर लिया तो 'चलता है सब' के दृष्टिकोण को हम भुला पाएंगे और एक नए युग की ओर कदम बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

योगी सरकार ने वापस लिया फैसला तो शिक्षकों में लौटी खुशी की लहर, कई दिनों से कर रहे थे विरोध

नोएडा के स्कूलों में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी लगने पर मुख्य सचिव ने कहा कि फिलहाल दो महीने के लिए इस व्यवस्था पर रोक लगाई गई है। दिक्कतों के समाधान के लिए कमेटी बनेगी। बता दें कई दिनों से शिक्षक डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे थे। इसको लेकर एक्स पर शिक्षकों ने बायकॉट डिजिटल हाजिरी व्यवस्था चलाया था।

ग्रेटर नोएडा। स्कूलों में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी लगने पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दो महीने के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही डिजिटल हाजिरी में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी का गठन किया गया है। शिक्षकों की ओर से कई दिनों से डिजिटल हाजिरी का विरोध किया जा रहा था। शिक्षकों का कहना था कि कई स्कूलों तक पहुंचने के लिए रास्ता तक नहीं था। इसके साथ ही स्कूलों में नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। वह लगातार आठ जुलाई से इसका विरोध कर रहे थे। हम सरकार के निर्णय का स्वागत करते है। शिक्षकों की एकता की जीत हुई। सरकार हमारी मूलभूत मुद्दों का समाधान करें। डिजिटल हाजिरी में बहुत सारी कठिनाई है। शिक्षकों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा।- निरंजन सिंह नागर,जिलाध्यक्ष जूनियर शिक्षक संघ एक्स पर शिक्षकों ने बायकॉट डिजिटल हाजिरी व्यवस्था (digital attendance system) पर हैशटैग चलाया था। शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया है। शिक्षकों का कहना है कि यह उनकी एकता की जीत है।

नोएडा में जाम से मिलेगी राहत! महामाया फ्लाईओवर से यहां तक सड़क चौड़ीकरण की तैयारी; पढ़िए पूरा अपडेट

परिवहन विशेष न्यूज

Noida और Greater Noida में इस स्थान पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिल सकती है। यहां सड़क चौड़ी करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने फिर से योजना बनानी शुरू कर दी है। हालांकि दो साल पहले भी इस योजना पर मंथन किया गया था लेकिन तब यह ठंडे बस्ते में चला गया था। अब फिर से इस पर मंथन शुरू हो गया है।

नोएडा। महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-14 ए Noida प्रवेश द्वार तक सड़क चौड़ी करने की कवायद एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण ने शुरू कर दी है।

सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक एजेंसी ने मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया।

नोएडा प्राधिकरण ने कुछ दिन पहले जारी किया था टेंडर

नोएडा प्रवेश द्वार सेक्टर-14ए के सामने से महामाया फ्लाईओवर तक अलग-अलग पांच कट के पास सड़क चौड़ी करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कुछ दिन पहले ही टेंडर जारी किया था। अभी महामाया फ्लाईओवर से नोएडा प्रवेश द्वार की तरफ जाने वालों की राह अभी भी कठिन है।

दो साल पहले भी बनी थी योजना

इस रास्ते को भी चौड़ा करने की योजना करीब दो साल पहले तैयार की गई थी लेकिन, तत्कालीन सीईओ रितु माहेश्वरी के जाते ही मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया।

इस योजना पर फिर से शुरू हुआ मंथन

अब एक बार फिर प्राधिकरण अधिकारियों न इस रास्ते को चौड़ा करने की योजना पर मंथन शुरू कर दिया है। एक निजी एजेंसी के जरिए सीईओ के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण में सामने आया कि इस हिस्से में काफी संख्या में पेड़ हैं जिनको शिफ्ट करना होगा।

कुछ हिस्से में पक्का निर्माण तोड़ना होगा

इसके अलावा दलित प्रेरणा स्थल के सामने कुछ हिस्से में पक्का निर्माण तोड़ना होगा। इसके अलावा यहां बने एफओबी का ढांचा भी बीच रास्ते में आ रखा है। ऐसे में इन तीनों अवरोधों को हटाना होगा।

पैसों के लेनदेन के कारण प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर मारी गोली, 7-8 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम

परिवहन विशेष न्यूज

पैसे के लेनदेन के चलते गुरुग्राम के गांव दौलताबाद स्थित द्वारका एक्सप्रेसवे पर बने एक प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस के अंदर घुसकर गोली मारी। पुलिस के मुताबिक न्यू कॉलोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार सहरावत उर्फ राजू व सचिन गुलाटी द्वारका एक्सप्रेस वे पर बने प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस में अपने दोस्त से मिलने पहुंचे थे। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गुरुग्राम। राजेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र के दौलताबाद में प्रॉपर्टी डीलर के आफिस में देर रात दो बजे पैसों के लेनदेन में झगड़ा हो गया। एक व्यक्ति ने न्यू कालोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी। गोली उसके पैर में लगी है। प्रॉपर्टी डीलर के साथ गए दोस्त से भी मारपीट की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित वहां से फरार हो गए। वहीं दोनों घायलों का इलाज नागरिक अस्पताल में चल रहा है।

पैसों के लेनदेन के कारण हुआ झगड़ा

पुलिस के अनुसार न्यू कालोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार सहरावत अपने दोस्त सचिन गुलाटी के साथ सोमवार देर रात द्वारका एक्सप्रेस-वे पर बने प्रॉपर्टी डीलर आफिस में अपने एक अन्य दोस्त से मिलने पहुंचे थे। बताया जाता है कि यहां पैसों के लेनदेन में राजकुमार और वहां मौजूद युवक के बीच झगड़ा हो गया।

आरोपितों ने राजकुमार को मारी गोली

इसके बाद आरोपितों ने राजकुमार को गोली मार दी। एक गोली उनके पैर में लगी है। वहीं राजकुमार के साथ गए सचिन से भी आरोपित ने लाठी-डंडों से मारपीट की। इसमें वह भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया।

अभी दोनों की स्थिति ठीक है। राजेंद्रा पार्क थाना प्रभारी इंस्पेक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान वहां कोई भी आरोपित नहीं मिला। इनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा।

गाजियाबाद: हिंडन नहर में डूब रहे युवक को सेवानिवृत नेवी के कमांडो ने बचाया

परिवहन विशेष न्यूज

इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के अभय खंड में हिंडन नहर में सोमवार को एक युवक डूब गया। नहर के आसपास काफी भीड़ लगी थी। लोग वीडियो बना रहे थे। जलकुंभी के बीच युवक फसा था। युवक का पिता मदद की गुहार लगा रहा था। अभी नोएडा से ड्यूटी कर लौट रहे अभय खंड तीन निवासी धनवीर सिंह नेगी रुके।

गाजियाबाद। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में हिंडन नहर में युवक को डूबता देखकर नेवी से सेवानिवृत मरीन कमांडो ने कूदकर बचा लिया। युवक के पिता को रोता उन्होंने मदद की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोगों ने उनकी सराहना की।

इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के अभय खंड में हिंडन नहर में सोमवार को एक युवक डूब गया। नहर के आसपास काफी भीड़ लगी थी। लोग वीडियो बना रहे थे। जलकुंभी के बीच युवक फसा था। युवक का पिता मदद की गुहार लगा रहा था।

अभी नोएडा से ड्यूटी कर लौट रहे अभय खंड तीन निवासी धनवीर सिंह नेगी रुके। उन्होंने नहर में कूदकर युवक की जान बचाई। उन्होंने बताया कि वह नेवी के मरीन कमांडो से सेवानिवृत हैं। युवक को बचाने के बाद ई-रिक्शा में ले गए। युवक कौन था कहा का था इसकी जानकारी नहीं हो सकी हुआ। इंदिरापुरम पुलिस ने मामले की जानकारी होने से इनकार किया है।

करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश,

नोएडा। Noida Police ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के आठ आरोपितों को अरेस्ट किया है। कोतवाली सेक्टर-49 पुलिस ने देश की नामी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में पांच महिला और गिरोह का सरगना शामिल है।

पुलिस के मुताबिक, ये लोग नोएडा में अलग-अलग स्थान पर ऑफिस खोलकर बेरोजगार लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। लोगों को जाल में फंसाने के लिए इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन जारी करते थे।

बताया गया कि नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार से एक लाख रुपये तक वसूल लेते थे। लोगों के शैक्षिक दस्तावेज जमा कराकर उन्हें फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र थमा देते थे।

धार्मिक कार्यक्रम में होने वाले हादसे रोकने होंगे

अशोक मधुप

उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के फुलरई में आयोजित भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ से 121 लोगों की मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं।

अभी हाथरस के धार्मिक आयोजन में मरने वालों के खून के छींटे साफ भी नहीं हुए थे कि जगन्नाथ पुरी में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में एक श्रद्धालु की मौत हुई। चार सौ घायल हुए। मुख्यमंत्री ने मरने वाले के परिवार को चार लाख रूपये की सहायता देने की घोषणा की। तो घायलों को मुफ्त इलाज के निर्देश दिए। घटना की जांच के आदेश भी दिये गए हैं। देश में हम धार्मिक आयोजनों को रोक नही सकते। ये हमारी आस्थाओं से जुड़े हैं। धार्मिक आयोजन रोज होतें हैं। गली-गली होते हैं। मुहल्ले-मुहल्ले होते हैं। देश काफी बड़ा है। कहीं न कही से बड़े आयोजन की खबरें आती रहती है। इन आयोजनों पर नजर रखनी होंगी, ऐसी व्यवस्था बनानी होंगी कि इनमें भगदड़ न मचें। अव्यवस्था न फैले। भगदड़ और अव्यवस्था फैलने की हालत में ऐसी व्यवस्था बनी हो कि दर्शक आराम में आयोजन स्थल से सुरक्षित निकल सके। हम धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन नहीं रोक सकते किंतु उन्हें हादसों रहित जरूर बना सकते हैं। इसी दिशा में कार्य होना चाहिए।

धार्मिक कार्यक्रमों में हादसेः-

- दो जुलाई को हाथरस में प्रवचन के दौरान भगदड़ में 121 मरे। गवाह का दावा कि गुरू जी के सेवक ने कहा चरण रज लेकर जाना। तब भगदड़ मची।

◪ इंदौर में राम नवमी के अवसर पर एक मंदिर में हो रहे हवन में पुरानी बावडी का स्लेब टूटने से 36 मरे।

◪ 2022 में माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ में 22 श्रद्धालु मरे।

◪ 2015 में आंध्रप्रदेश के गोदावरी नदी के घाट पर भगदड़ में 27 मरे।

- 15 अक्टूबर 2016 को वाराणसी में भीड़भाड़ वाले राजघाट गंगा पुल पर मची भगदड़ में 25 लोगों की मौत हो गई।

- तीन अक्तूबर 2014 को पटना के गांधी मैदान में दशहरा समारोह के समाप्त होने के बाद भगड़ में 32 जानें गई थीं।

◪ चार मार्च 2010 को यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मनगढ़ में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में मची भगदड़ में 63 लोगों की जान चली गई थी।

◪ 10 फरवरी, 2013 को प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 40 से ज़्यादा लोग मारे गए।

◪ पटना में गंगा के तट पर 19 नवंबर 2012 को छठ पूजा के दौरान अचानक अस्थायी पुल ढहने से भगदड़ मच गई थी, इसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी., इससे पहले आठ नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा किनारे हरकी पैड़ी पर मची भगदड़ में कम से कम 20 लोगों की जान चली गई थी।

◪ 4 मार्च 2010 को प्रतापगढ़ के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से 63 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए।

◪ 2008 में राजस्थान के जयपुर के चामुंडा मंदिर में बम की अफवाह के बाद मची भगदड़ में 250 लोग मरे।

◪ 2003 में महाराष्ट्र के नासिक के कुंभमेले में मची भगदड़ में 39 मरे।

◪ महाराष्ट्र के सतारा में साल 2005 की 25 जनवरी को मंधारदेवी मंदिर में सालाना तीर्थयात्रा के दौरान मची भगदड़ में 340 से अधिक श्रद्धालुओं की कुचलने से मौत हो गई थी।

यूपी के हाथरस स्थित सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के फुलरई में आयोजित भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ से 121 लोगों की मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ऐसा नहीं है, पहले भी भीड़भाड़ वाले स्थलों खासकर धार्मिक आयोजनों या धार्मिक स्थलों पर ऐसे हादसे होते रहे हैं। जिसके बाद जांच और कार्रवाई तो होती है पर कोई जिम्मेदार सबक

लेते नहीं दिखाई देते।

सनातन धर्म में 33 करोड देवी देवता हैं। हिंदू समाज की मान्यता है कि कण-कण में भगवान हैं। हम इतने आस्थावान है कण-कण में भगवान खोजते हैं। स्टोव तक हमारे देवता बन गए। दरअसल हमारे यहां हर गली मुहल्ले में ओझा हैं। भगत है। साधु हैं। सन्त हैं। ज्ञानी हैं। ओलिया हैं। फकीर है। जिसका जितना बड़ा मायाजाल और प्रचार तंत्र है, उसके उतने ज्यादा भक्त और शिष्य हैं। बड़ी बात यह है कि हिंदू समाज में पुरूषों से ज्यादा महिलाएं आस्थावान है। वे ही इन हादसों की शिकार होती है। हाथरस के धार्मिक कार्यक्रम में मची भगदड़ में मरने वालो में महिलाओं की ही संख्या ज्यादा है। इस कार्यक्रम के भक्त गुरू जी के प्रति इतने आस्थावान दिखाई दिए कि उन्हें हादसे का कोई मलाल नही। कुछ महिलाएं तो मीडिया से बात करते कहती नजर आंई कि वे भी मर जाती तो अच्छा होता। सीधे स्वर्ग मिलता। यहां भक्तों की इतनी श्रद्धा हो, वहां सरकार की सख्ती से ही इन हादसों को रोका जा सकता है।

आमतौर पर धार्मिक आयोजनों या धर्मस्थलों पर भारी भीड़ उमड़ती है। गहरी आस्था के चलते लोग अपने आराध्य के दर्शन करने या उनके बारे में सत्संग-प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। एक जनवरी 2022 को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े थे, जिससे भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 12 लोगों की जान चली गई थी, जबकि एक दर्जन घायल हुए। अपनी-अपनी आस्था के कारण धार्मिक स्थलों या आयोजन में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए वे किसी बात की परवाह नहीं करते, जरा सी भी ऊंच-नीच अफवाह भगदड़ का कारण बन जाती है। भारी भीड़ के बीच छोटी सी अफवाह भी बड़ा रूप ले लेती है। साल 2011 की 14 जनवरी को केरल के इडुक्की जिले में एक जीप सबरीमाला मंदिर में दर्शन कर रहे श्रद्धालुओं से टकरा गई थी। इसके बाद अफवाह फैली अफवाह से ऐसी भगदड़ मच गई कि इसमें 104 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। इसी तरह से बताया जा रहा है कि हाथरस में सत्संग स्थल पर सवा लाख लोग मौजूद थे। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अंदाजा न तो आयोजकों को था और न ही जिला प्रशासन को। इसलिए इस संख्या के हिसाब से मौके पर व्यवस्था ही नहीं की गई थी, जबकि सत्संग स्थल के अंदर की व्यवस्था आयोजकों को संभालनी थी और बाहर कानून-व्यवस्था पर प्रशासन और पुलिस को नजर रखनी थी। इस आयोजन के लिए जिला प्रशासन से बाकायदा अनुमति ली गई थी, इसके बावजूद सत्संग स्थल पर न तो श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग द्वार थे और न ही वीआईपी यानी भोले बाबा को भीड़ से सुरक्षित अलग रास्ते से निकालने के इंतजाम किए गए थे। ऐसे में बाबा जब सामने दिखे तो भीड़ उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ने लगी और बेकाबू हो गई। चश्मदीदों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि सत्संग स्थल पर जमीन ऊबड़-खाबड़ थी। इसे समतल करने तक की जहमत नहीं उठाई गई थी। ऐसे में जब भीड़ निकलने लगी तो पैर ऊपर-नीचे होने से लोग गिरने लगे। इससे भगदड़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई। देश के कई धार्मिक स्थलों के परिसर तो काफी बड़े हैं पर मुख्य दर्शन या पूजा स्थल काफी छोटे हैं। इसमें एक साथ भीड़ का रेला आता है तो धक्के के कारण लोग एक-दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं। इस दौरान लोग खुद के शरीर को ही नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अगर एक व्यक्ति भी भीड़ में गिर जाता है तो लोग चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि भीड़ में किसी के गिरने, बेहोश होने या मौत की अफवाह फैलती है और बचने के लिए लोग भागने लगते हैं। भीड़ में शामिल लोग, खासकर बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं इस भगदड़ का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। इसके लिए स्थानीय प्रशासन भी कहीं न कहीं जिम्मेदार होता है, जो आस्था के आगे हाथ खड़े कर देता है। छोटे स्थल पर अधिक लोगों की भीड़ बढ़ने पर भी वह लोगों को रोकता नहीं है। हाथरस के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला। कहा जा रहा है कि हाथरस में अनुमति और आकलन से कहीं ज्यादा भीड़ पहुंच गई थी। इसके बावजूद प्रशासन तमाशबीन बना रहा और न तो आयोजन निरस्त किया और न ही लोगों को रोकने की कोशिश की। धार्मिक आयोजन में कई ऐसी हस्तियां पहुंचती हैं, जिनके कारण भारी भीड़ इकट्ठा हो सकती है तो आयोजक खुद को वीआईपी से भी बड़ा मानने लगते हैं। इसके कारण वे लोगों के साथ मनमानी करते हैं। उन्हें रोकते-टोकते हैं। इसके कारण लोगों में गुस्सा पनपने लगता है। कई बार पत्थरबाजी और तोड़फोड़ होती है तो कई बार वीआईपी के लिए बनाए गए मंच आदि पर भीड़ चढ़ जाती है। हाथरस की घटना में भी इस तरह का नजारा सामने आया। बताया जा रहा है कि बाबा के काफिले को निकालने के लिए वहां मौजूद श्रद्धालुओं को आयोजन की व्यवस्था संभालने लगे लोगों ने रोक दिया था, जबकि वे किसी भी कीमत पर बाबा के पास पहुंचना चाहते थे और मस्तक पर गुरूजी की चरणरज लगाना चाहते थे। इसी से भगभड़ मची।

हाथरस जनपद के सिंकराराऊ क्षेत्र में स्थित फुलरई मुगलगढ़ी में साकार नारायण विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग का मंगलवार को आखिरी दिन था। बाबा सत्संग खत्म कर बाहर जाने के लिए निकल रहे थे। उसी दौरान बाबा के पैर छूने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे, जो भीड़ के धक्के से गिर गए और लोग उनको कुचलते हुए निकलने लगे। इसके कारण भगदड़ मच गई और 121 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है।

इस घटना के लिए जिला प्रशासन और पुलिस से लेकर आयोजक तक कठघरे में हैं। व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एक कमेटी बना दी। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की अगुवाई में पूरी घटना की जांच होगी। इससे स्पष्ट होगा कि आखिर इतने बड़े हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? हर हादसे की जांच होती है किंतु उससे सबक नहीं लिखा जाता। सीख नहीं ली जाती है। इसी का कारण है कि हादसे होते रहते हैं। रथयात्रा के मृतक को सरकार ने चार लाख रूपये दिए। घायलों के उपचार की व्यवस्था की। हाथरस के हादसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मृतक को दो लाख और घायल को पचास हजार रूपया मुआवजा दिया है। यह मुआवजे की राशि सत्संग के आयोजकों और कार्यक्रम के गुरू जी से वसूली जानी चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम में सरकारी स्तर से होने वाली व्यवस्था का खर्च भी आयोजकों से लिया जाना चाहिए। जांच में दोषी पाये गए आयोजकों पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही हादसे रूक पाएंगे। अन्यथा नहीं।

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले ग्राहकों को सताती हैं 5 चिंताएं, अगर समाधान हो जाएँ तो हिट हो जाएगी ईवी की मार्केट

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प हैं और पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में कम खर्चीले भी हैं। लेकिन कुछ चुनौतियाँ हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है।

भारत में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या अभी भी कम है। खास तौर पर जब आप महानगरों से बाहर या छोटे शहरों में जाते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों से लंबी दूरी की यात्रा करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चार्जिंग प्वाइंट ढूँढना एक मुश्किल काम है। चार्जिंग में भी काफी समय लगता है, जो उन लोगों के लिए परेशानी का सबब है जिनके पास समय की कमी है।

इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरियाँ महंगी होती हैं और वाहन की कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं बैटरियों पर खर्च होता हैं। बैटरियों की रेंज भी सीमित होती है, जिसका मतलब है कि आप एक बार चार्ज करने पर कम दूरी तय कर पाएँगे। ठंड के मौसम में बैटरी की रेंज और भी कम हो सकती है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को पारंपरिक वाहनों की तुलना में कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। लेकिन बैटरी को बदलना महंगा हो सकता है, खासकर अगर यह वारंटी से बाहर हो।

हालाँकि इलेक्ट्रिक वाहन कार्बन उत्सर्जित नहीं करते हैं, लेकिन बैटरियों के निर्माण और निपटान का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है अन्यथा इलेक्ट्रिक वाहन वास्तव में पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

भारत में नेट-ज़ीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए ई-मोबिलिटी आरएंडडी रोडमैप पर जारी की गई रिपोर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने आज 16 जुलाई, 2024, मंगलवार नई दिल्ली के विज्ञान भवन एनेक्सी में ₹भारत के लिए ई-मोबिलिटी आरएंडडी रोडमैप₹ रिपोर्ट जारी की। आरएंडडी रोडमैप वैश्विक ऑटोमोटिव क्षेत्र की विस्तृत क्षितिज स्कैनिंग और भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकी आवश्यकताओं की पहचान करने के बाद तैयार किया गया है। यह अनुसंधान परियोजनाओं को चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है: ऊर्जा भंडारण सेल, ईवी एग्रीगेट्स, सामग्री और रिसाइकिल, चार्जिंग और ईंधन भरना, और साथ ही अगले पांच वर्षों में आत्मनिर्भर बनकर वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए रास्ता बताता है। स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है।

हाइब्रिड मोड में आयोजित आधिकारिक शुभारंभ कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, ई-मोबिलिटी (सीजीईएम) पर सलाहकार समूह के सदस्यों, उद्योग और थिंक टैंक के प्रतिनिधियों और प्रेस और मीडिया के सदस्यों ने भाग लिया।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के वैज्ञानिक सचिव डॉ. परविंदर मैनी, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे के महानिदेशक डॉ. रेजी मथाई, नॉन-फेरस मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (एनएफटीडीसी), हैदराबाद के निदेशक डॉ. के. बालासुब्रमण्यम सहित अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

अपने उद्घाटन भाषण में प्रो. सूद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करना है ताकि 2070 तक शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धता प्राप्त की जा सके। इस दृष्टिकोण के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाना, स्वदेशी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का निर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ई-मोबिलिटी वैल्यू चेन आयात पर बहुत अधिक निर्भर करती है। प्रो. सूद ने ई-मोबिलिटी वैल्यू चेन के भीतर आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने और ऑटोमोटिव क्षेत्र में घरेलू अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पीएसए कार्यालय की सलाहकार डॉ. प्रीति बंजल ने ऑटोमोटिव क्षेत्र में एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम बनाने की दिशा में कार्यालय के महत्वपूर्ण प्रयासों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अगस्त 2022 में पीएसए कार्यालय ने 'ई-मोबिलिटी पर परामर्श समूह (सीजीईएम)' का गठन किया था, जो भारत में प्रचलित जीवाश्म ईंधन आधारित परिवहन क्षेत्र से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेजी से बढ़ने के लिए तकनीकी रोडमैप, अध्ययन, दस्तावेज तैयार करने के लिए सरकार, शिक्षाविदों और उद्योगों के विशेषज्ञों का एक पैनल है। रोडमैप दस्तावेज़ एआरएआई द्वारा सीजीईएम के समग्र मार्गदर्शन में तैयार किया गया है।

आईआईटी मद्रास में पीएसए फेलो और प्रैक्टिस के प्रोफेसर प्रो. कार्तिक आत्मनाथन ने भारत के लिए ई-मोबिलिटी आरएंडडी रोडमैप का सारांश प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैसे डीएसटी श्वेत पत्र ने वर्तमान आयात-निर्भर स्थिति से बाहर निकलने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों को सफलतापूर्वक पहचाना है और कैसे यह रोडमैप भविष्य में ऐसी ही स्थिति से बचने में मदद करता है क्योंकि समय के साथ तकनीक विकसित होती रहती है। प्रो. आत्मनाथन ने संकेत दिया कि विशेषज्ञों ने प्राथमिक उद्देश्य के रूप में प्रौद्योगिकी परिनियोजन और बाजार नेतृत्व दोनों पर शोध परियोजनाओं की पहचान की है। राष्ट्रीय ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने पर उनके संभावित प्रभाव, निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्यान्वयन की व्यवहार्यता, बाजार प्रभुत्व और मौजूदा बुनियादी ढांचे और संसाधनों का लाभ उठाने की उनकी क्षमता के आधार पर शोध परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई।

प्रस्तुतियों के बाद अध्यक्ष ने प्रेस और मीडिया के सदस्यों के प्रश्नों और उत्तरों के लिए सत्र रखा। यह सामने आया कि ई-मोबिलिटी आरएंडडी रोडमैप भविष्य की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रास्ता तैयार करता है, जिसमें महत्वपूर्ण शोध पहलों की रूपरेखा दी गई है जो भारत को अगले पांच से सात वर्षों के भीतर वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखलाओं में अग्रणी के रूप में स्थापित करेगी। इस रोडमैप का उद्देश्य वर्तमान अनुसंधान और विकास ढांचे में महत्वपूर्ण गैप को भरना है। जबकि कई पहचानी गई परियोजनाओं को अभी वैश्विक सफलता हासिल करनी है, कुछ क्षेत्र पहले से ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हैं, जहां भारत को अभी तैयारी शुरू करनी है। इन परियोजनाओं को देश के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करने के लिए शामिल किया गया है ताकि अवसर आने पर उन क्षेत्रों में भविष्य के नवाचारों को आगे बढ़ाया जा सके।

अपने समापन भाषण में प्रो. सूद ने कहा कि भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और इसकी तेज़ वृद्धि को देखते हुए यह भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस प्रगति को देश के नेट-ज़ीरो विज़न के साथ जोड़ा जाना चाहिए और ऑटोमोटिव क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और नवाचार-संचालित विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने की ज़रूरत है।

ऑटोमोबाइल निर्यात में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ती हुई बढ़ा रही विदेशों में भारतीय वाहनों की मौजूदगी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारतीय ऑटो बाजार में तेजी से मजबूत हो रहे निर्यात बाजार को लेकर सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) की रिपोर्ट के अनुसार इस साल की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल-जून के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कुल 11.92 लाख वाहनों का निर्यात किया गया है, जबकि पिछले साल की दूसरी तिमाही में 10.32 लाख वाहनों का निर्यात हुआ था। इसे देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्यात बाजार में तेजी है। दोपहिया वाहनों ने विदेशी धरती पर भी अपनी पहुंच मजबूत की है। 2024 की पहली तिमाही में इस साल जनवरी से मार्च तक दोपहिया वाहनों के निर्यात में 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसका निर्यात अब 9.23 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। एक साल पहले तक इस अवधि में यह आंकड़ा 7.91 लाख था। वहीं अगर तिपहिया वाहनों की बात करें तो पिछले साल इस अवधि में 73,360 तिपहिया वाहनों का निर्यात हुआ था। यह आंकड़ा अब इस साल घटकर 71,281 रह गया है। अप्रैल से जून 2024 की अवधि में तिपहिया वाहनों के निर्यात में 3 फीसदी की कमी आई है। इसके अलावा कमर्शियल वाहनों का निर्यात एक साल पहले तक सालाना आधार पर 14,625 था, जबकि अब यह 8 फीसदी बढ़कर 15,741 के आंकड़े को पार कर गया है।

कार निर्यात की बात करें तो इस साल की दूसरी तिमाही में पिछले साल की समान अवधि में विदेश भेजी गई 1.52 लाख कारों के मुकाबले सालाना आधार पर 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यानी अप्रैल से जून तक कारों के निर्यात का आंकड़ा बढ़कर 1.8 लाख हो गया है। इसमें 69,962 कारों का निर्यात हुआ है। जिसमें मारुति सुजुकी की कारों की विदेश में सबसे ज्यादा मांग है। इसके मुकाबले पिछले साल 62,857 कारों का निर्यात हुआ था। जबकि अप्रैल-जून के बीच हुंडई मोटर कंपनी 42,600 कारों का निर्यात कर मारुति के बाद सबसे ज्यादा अपनी कारें विदेश निर्यात करने वाली

फेम 3 के तहत नई ईवी सब्सिडी योजना बजट 2024 में नहीं किया गया शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने अभी तक फेम 3 के तहत अपनी नई ईवी सब्सिडी नीति पर फैसला नहीं किया है। 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024 के दौरान इसे शामिल किए जाने की संभावना नहीं है।

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि फेम 3 को निकट भविष्य में लागू किए जाने की संभावना है।

मंगलवार 16 जुलाई को सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि फेम 3 योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और आगामी बजट सत्र के दौरान इसकी घोषणा होने की संभावना नहीं है।

उन्होंने कहा, ₹पहले से ही तैयारी का काम चल रहा है। सभी मंत्रालयों ने सिफारिश की है कि फेम 3 कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाए। भविष्य में, कुछ महीनों या कुछ दिनों में इसे लागू किया जाएगा। यह अंतिम चरण में है।₹

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स कम करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इंडस्ट्री को 2 लाख प्रशिक्षित लोगों की जरूरत, सरकार को साल 2030 तक हासिल करना है लक्ष्य

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माताओं के संगठन सियाम ने मंगलवार 16 जुलाई को कहा कि जब कोई नई तकनीक आती है और लोगों के जीवन में सफलतापूर्वक अपनी जगह बना लेती है, तो उस तकनीक के इर्द-गिर्द एक बड़ा कारोबार खड़ा हो जाता है। जहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। इलेक्ट्रिक वाहन भी ऐसा ही एक सेक्टर है। जैसे-जैसे लोग ईवी को अपना रहे हैं, इस सेक्टर को बड़े पैमाने पर काम मिल रहा है। इस सेक्टर को आने वाले दिनों में 2 लाख कुशल लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। साल 2030 तक कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की 30 फीसदी स्वीकार्यता के सरकार के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को उस समय तक दो लाख कुशल लोगों की जरूरत होगी।

उद्योग निकाय ने कहा कि कर्मचारियों को काम पर रखने और प्रशिक्षित करने के लिए कुल 13,552 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की उम्मीद है। भारतीय

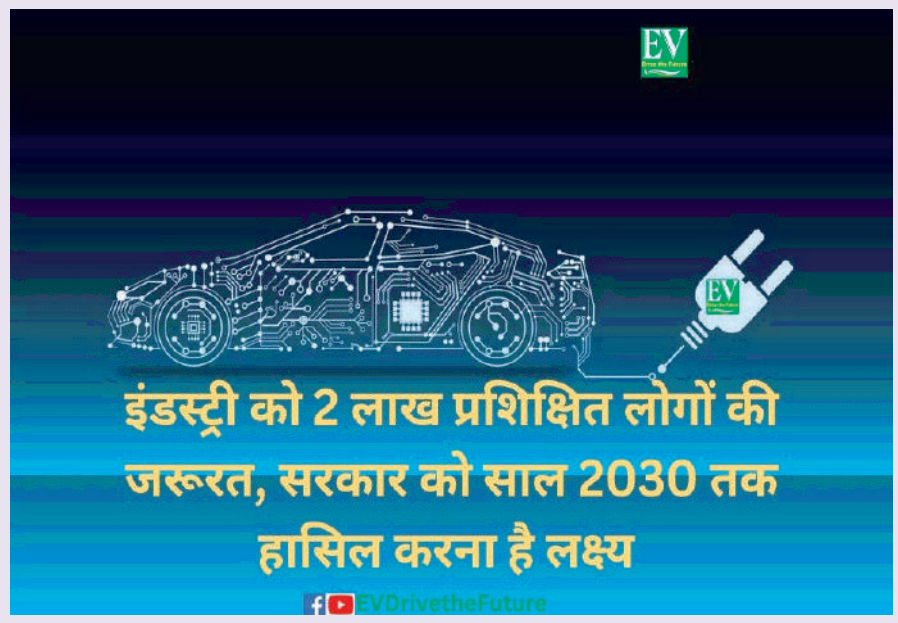

ऑटो उद्योग में ईवी से संबंधित कार्यबल को मजबूत करने पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए सियाम के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा, ₹ऑटो उद्योग के सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कुशल और सक्षम जनशक्ति की कमी है।₹ विनोद अग्रवाल, जो वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ भी हैं ने कहा कि बैटरी प्रौद्योगिकी-संचालित इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर डिजाइन के क्षेत्रों में विशेष रूप से कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, ''वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बनाए रखने और हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हमारे कार्यबल को कुशल बनाने की तत्काल आवश्यकता है।'' सियाम के उपाध्यक्ष शैलेश चंद्र ने कहा कि भारत को 2030 तक 30 प्रतिशत ईवी अपनाने के सरकार के मिशन को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कौशल वाले लगभग एक से दो लाख लोगों की आवश्यकता है।

हाइब्रिड कार निर्माताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा, कर छूट के लिए मापदंड करेंगे पूरे

परिवहन विशेष न्यूज

भारत की अग्रणी हाइब्रिड कार निर्माता कंपनियों मारुति सुजुकी इंडिया, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और होंडा कार्स इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित किया है कि उनकी मजबूत हाइब्रिड कारें राज्य नीति में निर्धारित सभी प्रदर्शन और दक्षता मापदंडों को पूरा करती हैं और 5 जुलाई के आदेश के तहत पंजीकरण शुल्क में छूट के लिए पात्र हैं।

11 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग के साथ एक बैठक के दौरान, तीनों कार निर्माताओं ने यह भी कहा कि मजबूत हाइब्रिड की बिक्री में वृद्धि पेट्रोल और डीजल कारों की कीमत पर होगी और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

पूरा मामला 5 जुलाई को शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश सरकार ने मजबूत हाइब्रिड पर 8-10 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क माफ करने का आदेश जारी किया। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं, मजबूत हाइब्रिड कारें नहीं जैसी कंपनियों ने इस कदम का विरोध किया है क्योंकि उनका मानना है कि मजबूत हाइब्रिड की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कोई भी प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक कार की बिक्री को प्रभावित करेगा। सूत्रों ने बताया कि इसके परिणामस्वरूप 9 जुलाई को सरकार ने एक नोटिस जारी कर कार कंपनियों से कहा कि यदि वे पंजीकरण शुल्क माफी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति (ईवीएमपीपी) 2022 में निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों का अनुपालन करना होगा। नोटिस में कार निर्माताओं को 11 जुलाई को बैठक के लिए भी बुलाया गया था।

ईवीएमपीपी 2022 के अनुसार केवल मजबूत हाइब्रिड कारें ही केंद्र सरकार की फेम-2 योजना में उल्लिखित प्रदर्शन और दक्षता विनिर्देशों को पूरा करती हैं और कर छूट के लिए पात्र हैं। राज्य सरकार की नीति 28 मार्च, 2019 को जारी फेम-2 अधिसूचना का हवाला देती है, जिसमें हाइब्रिड कारों के लिए प्रदर्शन पात्रता मानक शामिल हैं। फेम-2 योजना इस साल 31 मार्च को समाप्त हो गई। 11 जुलाई की बैठक के दौरान मारुति, टोयोटा किर्लोस्कर और होंडा कार्स ने राज्य सरकार को बताया कि उनकी मजबूत हाइब्रिड कारें फेम-II योजना में उल्लिखित मानकों को पूरा करती हैं और इस प्रकार ईवीएमपी 2022 के तहत पंजीकरण शुल्क माफी के लिए पात्र हैं। तीनों कंपनियों ने अपना मामला मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक दस्तावेज जमा करा दिए हैं।

भारत का ऑटोमोटिव उद्योग परिवर्तन की ओर, ई-मोबिलिटी अपनाने से होगा लाभ

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला है और कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने से देश को बहुत लाभ होगा।

मंगलवार 16 जुलाई को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के कार्यक्रम में कहा कि भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ईवी तैयार कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए चार्जिंग पर कार्यशाला₹ पर बोलते हुए कहा कि भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग परिवर्तनकारी युग के मुहाने पर है। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर वैश्विक बदलाव सिर्फ़ एक गुज़रता हुआ चलन नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण क्रांति है। उन्होंने कहा, ₹यह बदलाव कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल के साथ हमारे संबंधों को फिर से परिभाषित करने का वादा करता है।₹

एचडी कुमारस्वामी ने कहा, ₹भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने से बहुत कुछ हासिल होगा।₹ उन्होंने आगे कहा, ₹यह एक ऐसी यात्रा है जो आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा का वादा करती है।₹ भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य पर चर्चा करते हुए कुमारस्वामी ने उल्लेख किया कि यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार है।

यह वृद्धि विभिन्न ईवी प्रौद्योगिकियों में प्रगति और सुधार, उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि और सहायक सरकारी नीतियों द्वारा संचालित होने की उम्मीद है। कुमारस्वामी ने बताया, "भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है।" इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत न केवल वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बनाए रखे बल्कि ऑटोमोटिव उद्योग के सतत परिवर्तन में भी अग्रणी रहे।

हाल ही में पेश की गई भारत की नई ईवी नीति में भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन के प्रावधान हैं। सरकार की ईवी योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक तकनीक से लैस ईवी के लिए पसंदीदा विनिर्माण गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

नीति में न्यूनतम निवेश सीमा 4,150 करोड़ रुपये (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) निर्धारित की गई है और निर्माताओं को घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) के महत्वपूर्ण स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनिवार्य किया है कि विनिर्माण इकाई स्थापित करने के तीसरे वर्ष तक वाहनों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम 25 प्रतिशत घटकों को घरेलू स्तर पर खरीदा जाना चाहिए। संचालन के पांचवें वर्ष तक स्थानीयकरण का यह स्तर 50 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।

नए बजट में रोजगार सृजन पर हो जोर

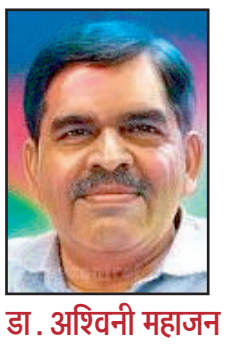

डा. अश्विनी महाजन

जैविक रसायन, प्लास्टिक और ईवी से संबंधित उपकरणों सहित चीन से आयात प्रतिस्थापन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) शुरू की जानी चाहिए। साथ ही रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा'

हालांकि, अंतरिम बजट फरवरी 2024 में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था, अब जुलाई 2024 में पूर्ण केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने का समय आ गया है। इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों के साथ तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जिसमें अर्थशास्त्री, किसान, एनबीएफसी, बाजार विशेषज्ञ और कई अन्य शामिल हैं। 19 जून को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आगामी बजट के बारे में अपना दृष्टिकोण देने के लिए आमंत्रित किया गया। सरकारी हलकों में लोग 8.2 प्रतिशत की उच्च जीडीपी वृद्धि, 9.9 प्रतिशत की तेजी से बढ़ते विनिर्माण, अप्रैल 2024 में सीपीआई मुद्रास्फीति के 4.82 प्रतिशत के साथ मुद्रास्फीति में कमी, डब्ल्यूपीआई में कमी, राजकोषीय घाटे के बजट अनुमानों से कम रहने, रुपए में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 1.4 फीसदी की बहुत कम दर गिरावट, और भुगतान संतुलन (बीओपी) में चालू खाता घाटा जीडीपी के बमुश्किल 0.7 फीसदी रहने को लेकर उत्साहित हैं। 2023-24 में, जून के पहले सप्ताह तक विदेशी मुद्रा भंडार 665.8 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, और जश्न मनाने के लिए बहुत से कारण हैं। अब मोदी 3.0 के सामने चुनौती इस वृद्धि को बनाए रखने के साथ-साथ मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने की है। बैठक में मौजूद सभी अर्थशास्त्री सरकार की राजकोषीय समझदारी, विनिर्माण संवृद्धि और भुगतान घाटे जैसे मुद्दों से निपटने की सराहना कर रहे थे। राजकोषीय समझदारी से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए यह एक पूर्व शर्त है। कम राजकोषीय घाटे को जारी रखने के बारे में आम सहमति थी। चूंकि सरकार ने पहले ही अंतरिम बजट 2024-25 में जीडीपी के 5.1 फीसदी के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव रखा है, इसलिए सरकार के लिए इससे विचलित होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिनके कारण सरकार को पूंजीगत व्यय, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के लिए अधिक धन की आवश्यकता हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च, पीएलआई योजना, विशेष रूप से नए क्षेत्रों में उसके विस्तार के साथ। इसके अलावा, बेरोजगारी की समस्या, विशेष रूप से शिक्षित युवा बेरोजगारी को संबोधित करने की भी तत्काल आवश्यकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोजगार : रोबोट टैक्स का सुझाव : बैठक में मौजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने नई तकनीक, खास तौर पर एआई के कारण नौकरियों के नुकसान के बारे में चिंता जताई और अन्य लोगों ने भी उनसे सहमति जताई। एक राय यह थी कि हालांकि, हम नई तकनीक के उपयोग से बच नहीं सकते और न ही बचना चाहिए, लेकिन चूंकि इससे नौकरियां जा रही हैं, इसलिए जो लोग लाभ उठा रहे हैं, उन्हें नुकसान उठाने वालों, यानी वे कर्मचारी जिनकी नौकरियां जा रही हैं या नौकरी के बाजार में नए प्रवेशकर्ता, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, की भरपाई करनी चाहिए। रोजगार सृजन का जिक्र करते हुए, यह सुझाव दिया गया कि रोबोट टैक्स की संभावना तलाशी जा सकती है, जिसका उपयोग विस्थापित श्रमिकों को पुनः कौशल प्रदान करने और पुनर्वासित करने के लिए किया जा सकता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि हाल ही में आईएमएफ द्वारा एक पेपर में उल्लेख किया गया है कि यद्यपि एआई समग्र रोजगार और मजदूरी को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन आईएमएफ ने यह भी कहा है कि 'श्रम बल के बड़े हिस्से को लंबे समय तक काम से बाहर रख सकता है, जो एक दर्दनाक संक्रमण की ओर इंगित करता है।'

एमएसएमई के लिए डिजाइन किया जाए पीएलआई : उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के पहले चरण की सफलता से उत्साहित, जिसने एपीआई, रक्षा उपकरण, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य में चीन पर निर्भरता को कम करने में मदद की, अर्थशास्त्रियों ने पीएलआई के अगले चरण को सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र (एमएसएमई) के इर्द-गिर्द डिजाइन करने का समर्थन किया। रोजगार सृजन पर नजर रखते हुए, अधिक संतुलित औद्योगिक विकास के लिए पीएलआई योजना को एमएसएमई के लिए डिजाइन करना महत्वपूर्ण है।

ई-उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाने की तैयारी : यह समझा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के परिणाम के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से डिजिटल उत्पादों पर सीमा शुल्क पर रोक समाप्त हो जाएगी। डिजिटल उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाने की तैयारी के रूप में, हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित सॉफ्टवेयर और अन्य डिजिटल वस्तुओं के लिए भारतीय सीमा शुल्क मैनुअल में विशिष्ट टैरिफ शीर्ष बनाकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर शून्य प्रतिशत के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र टैरिफ के साथ डिजिटाइज करने योग्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क शुरू कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया, सपोर्ट या ड्राइवर डेटा और अन्य डिजिटल उत्पाद शामिल हैं। इंडोनेशिया ने पहले ही यह कदम उठा लिया है। इससे डेटा एकत्र करने और 01-04-2026 के बाद उचित दरों पर सीमा शुल्क लगाने में सुविधा होगी, जब विश्व व्यापार संगठन द्वारा ई-ट्रांसमिशन के सीमा शुल्क पर लगाई गई रोक समाप्त हो जाएगी।

निजी निवेश को बढ़ावा देना : इसमें कोई संदेह नहीं है कि ई-उत्पादों पर टैरिफ लगाने से दीर्घकाल में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित उत्पादों में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कई अन्य उद्योगों और स्टार्टअप में भी निवेश को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है। घरेलू स्रोतों से इस निवेश को वित्तपोषित करने के लिए, हमें घरेलू निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल देने की आवश्यकता है। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैठक में जिन सुझावों पर चर्चा की गई, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं : 1. वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के प्रवाह में घर्षण को दूर करने के लिए सूचीबद्ध, गैर-सूचीबद्ध क्षेत्रों के बीच दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ समानता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। एआईएफ द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए निवेश को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर के अनुसार कर लगाया जाता है। वर्तमान में सूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ आम तौर पर 10 फीसदी की दर से और गैर-सूचीबद्ध शेयरों और अन्य परिसंपत्तियों पर 20 फीसदी की दर से कर लगता है। 2. जैविक रसायन, प्लास्टिक और ईवी से संबंधित उपकरणों सहित चीन से आयात प्रतिस्थापन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई योजना) शुरू की जानी चाहिए। 3. छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए घोषित रक्षा गलियारों में प्लग एंड प्ले सुविधाओं, कॉमन टूल रूम और आरएंडडी सुविधाओं के साथ औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा सकते हैं। उचित लागत पर रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए इसरो मॉडल को अपनाया जा सकता है। 4. हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रिवर्स फ्लिपिंग यानी देश में वापस लौटने वालों को अपेक्षित कर का भुगतान करना होगा और अधिकांश रिवर्स फ्लिपिंग करने वाले लोग इसे देने के लिए तैयार भी हैं, फिर भी लालफीताशाही और प्रक्रियाओं और ढेर सारे कागजी काम से जुड़े मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। चूंकि रिवर्स फ्लिपिंग एक बार का मामला है, इसलिए सरकार इसकी सुविधा के लिए एक पैकेज ला सकती है और जो लोग वापस लौट रहे हैं, उनके लिए असुविधा को कम कर सकती है।

संपादक की कलम से

लोकतंत्र में बंदूक संस्कृति

अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला किया गया। वह बाल-बाल बच गए। हमलावर को भी वहीं ढेर कर दिया गया। यह अमरीका ही नहीं, दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यह किसी भी लोकतंत्र में हो सकता है। कोई भी अतिवाद या उग्रवाद ऐसे हमले के लिए उकसा सकता है। इस पर गहन चिंतन-मनन, आत्ममंथन किया जाना चाहिए। अमरीका लोकतंत्र की जननी है। उसका लोकतंत्र प्राचीनतम है, लेकिन वहां बंदूक भी गोली-बिस्कुट और मूंगफली की तरह उपलब्ध है। औसतन हर हाथ में बंदूक, रिवॉल्वर है। अमरीका आत्म-रक्षा की दलीलें देता रहा है, लेकिन लोकतंत्र के साथ-साथ बंदूक-संस्कृति भी जारी है, यह विरोधाभास कैसे ढोया जा रहा है? लोकतंत्र में यह हत्यारा विरोधाभास भी मौजूद रहेगा, जो आने वाले किसी भी पल में, किसी और को, निशाना बनाया जा सकता है! इस सांस्कृतिक, सामाजिक और बेचैन गिरावट और पतन का अमरीकी नेताओं, राजनीतिक दलों और नागरिकों को लगातार विरोध करना चाहिए। ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति तो हैं। उनकी सुरक्षा-व्यवस्था मौजूदा राष्ट्रपति जितनी ही होती है।

रिपब्लिकन पार्टी ने उन्हें एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। चुनाव इसी नवंबर में होंगे, लिहाजा अमरीका में चुनावी मौसम छाया है। इस घटना की जांच कर रही एफबीआई का मानना है कि यह ट्रंप की हत्या करने का हमला था। हमले को लेकर कई सवाल सुरक्षा पर उठाए जा रहे हैं। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उन्हीं के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बहरहाल जिस 20 साल के नौजवान ने 120 मीटर से निशाना साध कर हमला किया, वह भी रिपब्लिकन पार्टी का सदस्य था और ट्रंप को 'गलत' मानता था। लोकतंत्र में आम नागरिक वोट के जरिए अपना अभिमत प्रकट कर सकता है और यही उसका बुनियादी अधिकार है, लेकिन अमरीका में लोकतंत्र के साथ राजनीतिक हिंसा का भी संबंध रहा है। राजनीति के अलावा, सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण भी हिंसात्मक रहे हैं, नतीजतन स्कूलों, बाजारों, सभा-कक्षों अथवा किसी समारोह के दौरान भी गोलीबारी चलाई जाती रही है। मौतें होती रही हैं। लोग बुरी तरह जख्मी भी होते रहे हैं। हमलावर की प्रवृत्तियों को मनोवैज्ञानिक अस्थिरता के आवरण में छिपाया जाता रहा है। अमरीका में पूर्व राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया है, ऐसे हमले अभूतपूर्व नहीं हैं। अमरीका में चार पदासीन राष्ट्रपतियों-अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैककिनले, जॉन एफ. कैनेडी-की हत्या तक की जा चुकी है। पांच राष्ट्रपतियों-बिल क्लिंटन, रोनाल्ड रीगन, जेराल्ड फोर्ड, फ्रेंकलिन रुजवेल्ट, थियोडोर रुजवेल्ट-पर भी हमले किए जा चुके हैं। यह कैसा लोकतंत्र और 'दुनिया का दादा' देश है, जो दुनिया को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के ज्ञान बांटता रहता है, लेकिन जहां 'बंदूक-संस्कृति' बिल्कुल सामान्य है। बंदूक बनाने वाले उद्योगपति इतने ताकतवर हैं कि न तो राष्ट्रपति बाइडेन कोई निर्णय ले पाए और न ही ट्रंप और उनकी पार्टी की सोच बंदूक-विरोधी है। जनवरी 6, 2021 की चेतावनी अमरीका कैसे भूल सकता है, जब ट्रंप-समर्थक भीड़ ने 'यूएस कैपिटल' (यूएस कांग्रेस) पर हमला किया था और अंदर घुस गई थी। उस पर क्या कानूनी कार्रवाई की गई, आज तक स्पष्ट नहीं है। वह अमरीकी लोकतंत्र और संसद पर सबसे भीषण प्रहार था। लोकतंत्र में भीड़ इतनी हिंसात्मक कैसे हो गई, जबकि उसके मानवाधिकार सुरक्षित हैं? हाल ही में अमरीका में 'राजनीतिक हिंसा' पर एक जनमत किया गया। आश्चर्य है कि 10 फीसदी लोगों ने जवाब ट्रंप के खिलाफ दिया कि ऐसे नेताओं को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए ऐसा ही बल इस्तेमाल करना न्यायसंगत है। यह भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन हिंसा न हो। बहरहाल अमरीका में ही नहीं, दुनिया के देशों में लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो चुनाव प्रचार का तरीका भी सभ्य होना चाहिए।

राय

हारे तो हम-2

चुनावी जीत के मायनों में सराबोर राजनीति के लिए बढ़ता स्थान दरअसल जनता में संकीर्णता पैदा कर रहा है। सत्ता की बढ़ती मर्जी में जनता की ख्वाहिशों का चित्रण, पुनः राज्य की हकीकत में झांक रहा है, तो फैसलों के पक्ष में तर्क बदलेंगे और कसौटियां भी नए मानदंडों में कसी जाएंगी। कुछ इसी तरह का फैसला 125 यूनिट बिजली की सीमा तक मुफ्तखोरी पर जब उकसा रहा था, हम तब भी हार रहे थे क्योंकि ऐसी कोई मांग जनता ने तो नहीं की थी। अगर तब गारंटियों के युद्ध में मुफ्त बिजली की सीमा तीन सौ यूनिट करने की प्रतिस्पर्धा हो रही थी, तो राज्य के आर्थिक संसाधन हिमाचल के पूरे नागरिक समाज को उलाहना दे रहे थे। हर चुनाव का भुगतान होता है और हिमाचल की चुनावी उदारता ने समाज की मानसिकता को हमेशा हरा दिया। हम चुनावी घोषणाओं के मनमोहन से हारते हैं। इन उपचुनावों में भी मनमोहन की प्रक्रिया में दो सीटों में कांग्रेस की मुद्रा जनता को जीत गई, लेकिन हमीरपुर का ताज सत्ता नहीं पहन पाई। ऐसे में जनता की जय विजय को परखना मुश्किल है। अपने जिला के मुख्यमंत्री को हमीरपुर की जनता ने क्या संदेश दिया है, इसके ऊपर सामाजिक चर्चा इसलिए जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक अर्थों में इस बार उपचुनाव थे ही सत्ता के पक्षधर। हमीरपुर से ज्यादा दूर नहीं है देहरा, तो वहां की जनता सत्ता के नजदीक हो गई यानी इस बार सरकार अगर कांगड़ा में नजर आई तो देहरा के मैदान पर सजने वाले मंच तुर्रा पहन कर संबोधन करेंगे। वैसे हर जीता हुआ सत्तापक्ष का विधायक अपने-अपने हलके को मॉडल की संज्ञा में कृपा दान देना चाहता है, लेकिन इस बार सत्ता में उनका आटा गीला ही रहा।

सत्ता का आटा बागी विधायकों के पानी ने गीला कर दिया और बाकी जो बचा उसे उपचुनावों ने पानी-पानी कर दिया। उपचुनावों से पहले तमाम बागी विधायक कम से कम कांग्रेस की सत्ता में तो थे। तब जनता के भ्रम, आश्वासन व सपने भी कांग्रेसी थे, लेकिन भाजपा के सपनों का द्वंद्व इनमें से छह को 'पूर्व' कर गया, लेकिन जो तीन लौट आए वहां अब असली परख होगी। देखते हैं अब हमीरपुर, धर्मशाला और बड़सर में कांग्रेस से छीना गया हाथ अब ताली कैसे बजाता है। ऐसे में लोकतंत्र में क्या देहरा की जीत वास्तविक होगी और हमीरपुर में नागरिक स्वाभिमान पस्त हो जाएगा। बहरहाल पिछले कुछ महीनों की सियासी उथल पुथल ने सरकार के मंथन को चुनावी बना दिया और फैसलों की अहमियत भी काम चलाऊ ही रही। अलबत्ता अब हकीकत से भरे फैसले आएंगे और जिसकी शुरुआत बिजली के 125 यूनिट कर रहे हैं। इससे अगर 15 सौ करोड़ बचेंगे तो यह धन बड़े काम का है, लेकिन समाज का दोहन अब चुनावी शर्तें करती हैं। सामान्य समाज के बनिस्पत हिमाचल में कर्मचारी वर्ग हमेशा से विशेषाधिकार प्राप्त रहा है। सरकारें अपने वित्तीय संतुलन, बजटीय मर्यादा और राज्य की औकात से कहीं अधिक जब कर्मचारी वर्ग की खुशामद में लगाती हैं, तो कहीं प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा-समुदाय हार रहा होता है। हार रहे होते हैं बेरोजगार, छोटे दुकानदार व स्वरोजगार की तलाश में निकले युवा क्योंकि सामने सरकारें केवल सरकारी कर्मचारियों की हिफाजत में प्रत्येक लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर रही होती हैं। हम हर नए स्कूल, अनावश्यक कालेज-विश्वविद्यालय की पढ़ाई में हार रहे हैं। मेडिकल कालेजों या बड़े अस्पतालों की पर्ची पर जब फेल होकर निजी या बाहरी अस्पतालों में इलाज करा रहे होते हैं, तो हार रहे होते हैं। सरकारी राशन के डिपो में बढ़ती सबसिडी के सामने हमारा खेत हार रहा होता है। हम अवारा जानवरों, वन्य प्राणियों और बंदरों की बढ़ती तादाद के बीच कब से हार रहे हैं, लेकिन अब तो सरकारों की नजर में यह हकीकत है ही नहीं। आश्चर्य यह कि विभागीय आंकड़ों में कृषि, सब्जी, फलोत्पादन और दुग्ध उत्पादन निरंतर बढ़ रहे होते हैं और हम कहीं बाजार में आटे-चावल, दूध-ब्रेड के आयातित पैकेट खरीदकर हार रहे होते हैं। सरकार कर्ज लेकर विकास कर रही है, लेकिन प्रदेश के निर्माण में हारती गुणवत्ता के सामने हमारा भविष्य हारने लगा है।

विद्वता के पर्याय थे डा. गणपति चंद्र गुप्त

साहित्येतिहास के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी भाषा तथा साहित्य का विश्वकोश भी तैयार किया जो एटलांटिक पब्लिशर्ज से दो खंडों में प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी के अनेक लेखकों की प्रविष्टियां हैं। प्रेमाख्यानों से संबंधित लगभग दो सौ प्रविष्टियां मेरी भी हैं। डा. गुप्त का देहावसान 21 मई 1996 को बीकानेर में हुआ'

स्वतंत्रता के बाद भारत में हिंदी के प्रति अद्भुत उत्साह था।

विश्वविद्यालयों में भी इस उत्साह की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। नई पुस्तकों के निर्माण और शोध में गंभीर विषयों का चयन इस बात का प्रमाण था। पंजाब यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में दिग्गज लोग उपस्थित थे। डा. इंद्रनाथ मदान, डा. धर्मपाल मैनी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा. मैथिली प्रसाद भारद्वाज, डा. गणपति चंद्र गुप्त, डा. सरनदास भनोत जैसे मनीषी विद्वान हिंदी के प्रचार-प्रसार को नए आयाम दे रहे थे। डा. मदान लाहौर से आए थे। उनकी पीएचडी का शोध प्रबंध मुंशी प्रेमचंद के कथा साहित्य पर था, जो अंग्रेजी में लिखा गया था। डा. गुप्त साहित्य में श्रेष्ठता की तलाश में राजस्थान के जिले सीकर से पहले जालंधर और फिर चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में आए। यह वह समय था सन-साठ-बासठ का, जब प्रोफेसरों में गजब की होड़ लगी हुई थी, एक-दूसरे से बेहतर काम करने और आगे निकल जाने की। डा. गणपति चंद्र गुप्त का जन्म 16 जुलाई, 1928 को राजस्थान के सीकर में हुआ, परंतु एक बार वह पंजाब आ गए तो फिर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के ही होकर रह गए। आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान में भी कुछ समय निदेशक के पद पर रहे। वह निश्चित रूप से एक मेधावी छात्र थे। एमए हिंदी में प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान और फिर पीएचडी करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से डी. लिट करने वाले पहले विद्वान थे।

उन्हें डी. लिट की उपाधि 'साहित्य विज्ञान' पर मिली, जिसमें उन्होंने फिजिक्स का काइनेटिक एनर्जी सिद्धांत लगाकर साहित्य विज्ञान की व्याख्या की और साहित्य विज्ञान के लिए लिटरोलोजी शब्द सुझाया। हिमाचल के जिन चार लोगों को उनके निर्देशन में पीएचडी करने का सौभाग्य मिला, उन चार में मैं भी शामिल था और अन्य तीन थे डा. कमला माहेश्वरी, डा. शमी शर्मा और नादौन से डा. ब्रह्मदत्त शर्मा। डा. गणपति चंद्र गुप्त मध्यकालीन संत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। उनका शोध 'बिहारी सत्सई और श्रृंगार परंपरा' प्रेम के नए अर्थों को संदर्भित करने का अनूठा प्रयास था। डा. नगेंद्र ने जो 'हिंदी साहित्य का इतिहास' संपादित किया, उसमें प्रेमाख्यान परंपरा पर विशेष अध्याय डा. गुप्त ने ही लिखा है। मुझे भी उन्होंने 'जायसी पूर्व रचित हिंदी प्रेमाख्यानों के आधार पर हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के उद्गम स्रोत, स्वरूप एवं प्रवृत्तियों का विवेचन' विषय पीएचडी शोध के लिए दिया और मुझे भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विश्व की बारह अन्य भाषाओं के प्रेमाख्यानों का इतिहास और मूल ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उस समय तो बुरा लगता है कि गुरु जी ने अर्क ही निकाल लिया, परंतु बाद में अच्छा लगता है क्योंकि श्रम सदा सार्थक होता है। एक उनका तरीका था कि संबद्ध विषय के विद्वानों को पत्र लिखवाते थे ताकि नई बातें, नए सूत्र हाथ लगें। फिर वे दूरदराज के पुस्तकालयों में भी सामग्री एकत्रित करने के लिए भेजते थे। अपने आप सब कुछ पक जाता था। आज रिसर्च का ढंग ही बदल गया है। मूल पुस्तकें भी नहीं खरीदते शोधार्थी और कट-पेस्ट से ही काम चला लेते हैं। अपवाद अब भी होंगे। डा. ब्रह्मदत्त ने कबीर पर, डा. शमी शर्मा ने तुलसीदास और सूर साहित्य पर शोध किया था। सन-1965 में डा. गुप्त का 'हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास' प्रकाशित हुआ।

क्लिष्ट होने के कारण खूब चर्चा हुई और अनेक यूनिवर्सिटियों ने इसे पाठ्यक्रम में संस्तुत किया। इनके साहित्यिक निबंध भी बहुत लोकप्रिय हुए। हिंदी साहित्य एवं साहित्यकार ग्रंथ भी अपनी मौलिकता के कारण कीर्तिमान स्थापित करने में सफल हुआ। डा. गुप्त को गुस्सा भी बहुत आता था। लेकिन फिर कुछ समय बाद सहज हो जाते थे।

मन के बड़े निर्मल और छात्रों के लिए बड़े स्नेही। अपनी अवधारणाओं में एकदम अटल। और हर बात को तर्क और युक्तियों से काट देते। उन्होंने डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह तर्क कभी स्वीकार नहीं किया कि हिंदी के प्रेमाख्यान फारसी मसनवियों से प्रभावित या प्रेरित थे। मेरे निष्कर्ष भी विश्व प्रेमाख्यान परंपरा के आधार पर ऐसे ही थे। और मेरे परीक्षक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही थे। उन्हीं के मतों का मैंने खंडन किया था, परंतु वाइवा में उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा- 'आपने खूब श्रम किया है और विश्व भर के प्रेमाख्यानों को छान मारा है। यही अनुसंधान का लक्ष्य होना चाहिए।' यह उनकी महानता थी। मेरे दूसरे एग्जामिनर विश्व भारती विश्वविद्यालय के डा. रामपूजन तिवारी थे। दोनों बड़े लोग थे, इसीलिए थिसिस मूल्यांकन में तीन वर्ष लग गए। आजकल दो मास में पीएचडी का रिजल्ट आ जाता है। कितना बदल गया है समय। डा. गुप्त सौभाग्यशाली थे कि शांता कुमार सन-1978 में हिमाचल के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हिंदी को बढ़ावा देते हुए डा. गुप्त को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। बाद में डा. गुप्त कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रहे, परंतु बड़े चतुर-चालाक न होने के कारण उन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति का पद भी समय से पूर्व ही छोडऩा पड़ा। डा. गुप्त पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी रहे, फिर रिजनल सेंटर शिमला में और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी के ही रिजनल सेंटर रोहतक में हिंदी के प्रोफैसर रहे।

वह केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक भी रहे और राजस्थान अनुसंधान संस्थान के निदेशक भी रहे। साहित्येतिहास के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी भाषा तथा साहित्य का विश्वकोश भी तैयार किया जो एटलांटिक पब्लिशर्ज से दो खंडों में प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी के अनेक लेखकों की प्रविष्टियां हैं। प्रेमाख्यानों से संबंधित लगभग दो सौ प्रविष्टियां मेरी भी हैं। अभी डा. गुप्त की और भी बहुत सी योजनाएं थीं। डा. गुप्त का देहावसान 21 मई 1996 को बीकानेर में हुआ, जहां वह अपने ससुराल के शहर में वापस चले गए थे। उनकी पांच मेधावी संतानें थीं। सबसे बड़े बेटे प्रोफैसर रमेश गुप्त का देहावसान कोरोना में हो गया। अन्य परिवारजन अपने-अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। विलक्षण प्रतिभा के धनी डा. गणपति चंद्र गुप्त प्रेरणा पुंज थे, हिंदी साहित्य के पुरोधा थे। गुरु जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन।

डा. सुशील कुमार 'फुल्ल'

पीए सिद्धार्थ

साहिब फुर्सत में हैं

पता नहीं बड़े साहिब ने मौसम फिल्म के लिए गुलज़ार का लिखा गाना 'दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन' सुना है या नहीं, पर बड़े साहिब जब भी किसी मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, फुर्सत के रात दिन जीने लगते हैं। आधे घंटे की मीटिंग जब चार घंटे बाद खत्म होती है तो बाहर निकलने पर बाकी अफसरों पर हमदर्द का चुस्ती-फुर्ती लाने वाला टॉनिक सिंकारा भी काम नहीं करता। बेचारे निढाल से निकलते हैं मीटिंगों से। कुछ मरे-मरे से, कुछ बुझे-बुझे से। पर बड़े साहिब हैं कि उतने ही तरोताज़ा होते हैं जितना मीटिंग में जाने से पहले होते हैं। बिल्कुल ताज़ा गुलाब की तरह। ख़ुशबू भले न हो, पर बड़े साहिब खिले-खिले तो वैसे ही लगते हैं। यूं भी आदमी चाहे बड़ा उम्र के हिसाब से हो या पद के हिसाब से, जैसे-जैसे बड़ा होने लगता है उसकी ख़ुशबू गायब होती जाती है। मीटिंगें कई तरह की होती हैं। भारत सरकार के मंत्रालयों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है-बड़ा मंत्रालय, मझोला मंत्रालय और छोटा मंत्रालय। प्रायः जितना बड़ा मंत्रालय होता है, उसके बड़े बाबू के पास मीटिंग में बैठने की फुर्सत उतनी कम होती है। छोटा मंत्रालय मतलब फुर्सत ही फुर्सत। छोटे मंत्रालय के बड़े बाबू और बड़े मंत्रालय के बड़े बाबू की तनख्वाह भले एक जैसी होती है, पर फर्क होता है तो केवल फुर्सत का। छोटे मंत्रालय के बड़े बाबू के पास फुर्सत ही फुर्सत होती है। भारत सरकार ने इन मीटिंग के लिए बाक़ायदा कान्फ्रेंस हॉल बनवाए हैं। ग़ौर से देखने पर पता चलता है कि यह कान्फ्रेंस हॉल पुराने ज़माने की चौपाल का आधुनिकतम रूप हैं।

बस फर्क है तो इतना कि अब चौपाल चारदीवारों के अंदर जमती है, सामने बड़ी सी टीवी स्क्रीन होती है जिसमें ज़रूरत पडने पर या जब बड़े बाबू किसी को गरियाना चाहें, फील्ड के अधिकारियों या दफ्तरों को भी घसीटा जा सकता है। मीटिंग हो तो चाय-पानी भी होगा ही। इससे कैंटीन वाली रोज़ी-रोटी भी चलती है और स्टाफ का गला भी तर रहता है। ऐसे ही छोटे मंत्रालय के एक बाबू हैं, झुन्नू लाल जी। हैं तो संयुक्त सचिव के पद पर, पर आजकल उनके पास एक ऐसी क्षेत्रीय परिषद का अतिरिक्त कार्यभार भी है, जिसमें सचिव का पद है। यह पद भारत सरकार के मंत्रालय के संयुक्त सचिव और सचिव के बीच का है अर्थात अतिरिक्त सचिव स्तर का है। पर जब यह अतिरिक्त सचिव नाम का जीव क्षेत्रीय परिषद में विराजमान होता है तो उसे सचिव के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे में झुन्नू लाल का सचिव होना, उनमें कुछ और बड़ा होने का एहसास भर देता है। दिल्ली में गर्मी बढने पर झुन्नू लाल जी अपनी पीठ की घमौरियां ठीक करने के लिए शिलांग जैसी जगह में ठंडी हवा खाने चले आते हैं। पर उनका आना क्षेत्रीय परिषद के बाबुओं को बहुत खलता है। अब खले भी क्यों न? भला यह भी कोई बात हुई कि भारत सरकार अपने कर्मियों से पांच दिन सुबह नौ बजे से साढ़े पांच तक काम लेती है और बदले में फाईव डे वीक देती है। पर झुन्नू लाल जी हमेशा दिल्ली से वीरवार को सुबह साढ़े चार बजे उड़ते हैं और शिलांग में ग्यारह बजे से पहले दफ्तर पहुंच जाते हैं। आते ही आदेश निकलवा देते हैं कि चूंकि बड़े बाबू आए हैं, इस बार शनिवार और इतवार को भी ठीक नौ बजे दफ्तर लगेगा। क्षेत्रीय परिषद के बेचारे बाबू मन मसोस कर रह जाते हैं। दफ्तर में बड़े बाबू झन्नाते हैं और घर में बीवी कहती है, 'अजी! आप तो अपना बिस्तर भी दफ्तर में ही लगा लो। आप तो इस हफ्ते पीवीआर ले जाने वाले थे न। मुन्ने की स्कूल की यूनिफॉर्म भी लेनी थी। आप लोग क्या अपने बॉस से इतना भी नहीं कह सकते कि छुट्टी वाले दिन दफ्तर कैसा?' अब बेचारा बाबू अपनी बीवी से कैसे कहे कि बल एकता में होता है। एक अकेला बोलेगा तो बड़ा बाबू बोलेगा, 'क्या बोलता है। मैं तो महीने में एक बार आता हूं तुम्हारी वीक एंड खराब करने। कहो तो अगले हफ्ते भी टिक जाऊं?'

पीए सिद्धार्थ

सोने-चांदी की कीमतों में एकदम से हुई बढ़ोतरी, जानिए आज के ताजा दाम

सोमवार को सोने के भाव 75150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए थे। राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना क्रमश 75700 रुपये प्रति 10 ग्राम और 75350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोला गया। इसके अलावा चांदी की कीमत भी 400 रुपये की तेजी के साथ 94400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सत्र में चांदी 94000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत रुख के साथ ही आभूषण विक्रेताओं की ताजा लिवाली के चलते स्थानीय बाजार में मंगलवार को सोना 550 रुपये की तेजी के साथ 75,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं,चांदी की कीमत भी 400 रुपये की तेजी के साथ 94,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

सोने-चांदी के लेटेस्ट प्राइस

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार को सोने के भाव 75,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए थे। राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना क्रमशः 75,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और 75,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोला गया। व्यापारियों ने सोने की कीमतों में तेजी का श्रेय घरेलू बाजार में स्थानीय आभूषण विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की मांग में तेजी को दिया।

इसके अलावा चांदी की कीमत भी 400 रुपये की तेजी के साथ 94,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सत्र में चांदी 94,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। दरों में कटौती की उम्मीदों के चलते सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमओएफएसएल) के कमोडिटी रिसर्च के वरिष्ठ विश्लेषक मानव मोदी ने कहा कि सोमवार को कोई प्रमुख डेटा पॉइंट निर्धारित नहीं था। हालांकि, यूएस फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की टिप्पणियां सुर्खियों में रहीं। फेड के अध्यक्ष पॉवेल ने कहा कि दूसरी तिमाही के आंकड़ों ने नीति निर्माताओं को इस बात का अधिक भरोसा दिया है कि मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के 2 प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।

पॉवेल ने दोहराया कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक दरों में कटौती करने की जल्दी में नहीं है, लेकिन उन्होंने श्रम बाजार में नरमी और घाटे में वृद्धि के बारे में भी चिंता जताई। मोदी ने कहा कि इस सप्ताह, व्यापारी अमेरिकी खुदरा बिक्री, औद्योगिक उत्पादन और कुछ आवास संख्याओं जैसे महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट पर नजर रखेंगे, जो समग्र आर्थिक स्वास्थ्य पर स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं।

विदेशी बाजार का हाल

विदेशी बाजार की बात करें, तो कॉमेक्स पर हाजिर सोना 2,436 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले दिन से 28 डॉलर प्रति औंस की बढ़त दर्ज करता है। इसके अलावा, चांदी भी 30.77 डॉलर प्रति औंस पर बोली गई। पिछले सत्र में यह 30.68 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई थी।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार के अनुसार, वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंचने के कारण ईटीएफ की मांग और सट्टा खरीद के बीच तेजी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि सोने में सकारात्मक कारोबार जारी है।

यूपीआई पर मिल रही क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा, ऐसे उठाएं बेनिफिट

परिवहन विशेष न्यूज

आज के समय में यूपीआई पेमेंट ट्रांजेक्शन की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इसकी संख्या में और बढ़ोतरी के लिए जल्द ही सभी यूजर्स के लिए यूपीआई क्रेडिट लाइन सुविधा शुरू हो जाएगी। वर्तमान में यह फीचर कुछ बैंक में ही उपलब्ध है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि यूपीआई क्रेडिट लाइन फीचर क्या है?

नई दिल्ली। आज के टाइम में कैश रखना कोई पसंद नहीं करता है। ज्यादातर लोग लेनदेन के लिए यूपीआई (UPI) का इस्तेमाल करते हैं। 5 रुपये के भुगतान के लिए भी लोग यूपीआई को चुनते हैं। वैसे तो यूपीआई से पेमेंट के लिए आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तब भी अब आपको घबराने की जरूरत नहीं।

जी हां, अब यूपीआई एकदम क्रेडिट कार्ड (Credit Card) की तरह काम करेगा। जल्द ही यूपीआई की क्रेडिट लाइन (UPI Credit Line) की सुविधा शुरू होने वाली है। कई बैंकों में यह सुविधा शुरू हो गई है। वर्तमान में यूपीआई क्रेडिट की सुविधा एक्सिस बैंक (Axis Bank), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), इंडियन बैंक (Indian Bank) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों को मिल रही है।

उम्मीद है कि जल्द ही यह सुविधा बाकी यूपीआई यूजर्स को भी मिलने लग जाएगी।

क्या है यूपीआई क्रेडिट लाइन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यूपीआई क्रेडिट लाइन को मंजूरी दे दी है।यह यूपीआई का नया फीचर है। यूपीआई क्रेडिट लाइन एक तरह का सिस्टम है। यह सिस्टम एक तरह से क्रेडिट कार्ड या फिर प्री-अप्रूव्ड लोन (Pre-Approved Loan) की तरह काम करता है। इसमें यूजर्स एक तय लिमिट तक का लोन ले सकते हैं। इसमें यूजर्स जितना खर्च करेगा उतनी राशि पर ही ब्याज लगेगा।

क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें भी यूजर्स को एक निश्चित समय तक पेमेंट करना होगा। यूपीआई क्रेडिट लाइन में यूजर को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

आपको बता दें कि यूपीआई क्रेडिट लाइन के लिए यूजर को बैंक में अप्लाई करना होगा। बैंक ग्राहक के सिबिल स्कोर के आधार पर ही क्रेडिट लाइन का अप्रूवल देगी। अप्रूवल मिल जाने के बाद यूजर अकाउंट में पैसे न होने के बावजूद आसानी से यूपीआई कर सकेंगे।

यूपीआई क्रेडिट लाइन के फायदे

ग्राहक को अलग-अलग क्रेडिट कार्ड रखने की जरूरत नहीं हैं।

क्रेडिट कार्ड मिलने में समय लगता है जबकि क्रेडिट लाइन का अप्रूवल तुरंत मिल जाएगा।

यूजर को यूपीआई पेमेंट करते वक्त बैंक अकाउंट में अमाउंट की टेंशन नहीं होगी।

आपात स्थिति में क्रेडिट लाइन वित्तीय मदद करेगा।

निवेश के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है?, यहां समझें पूरा गणित

SIP vs PPF जब भी कोई व्यक्ति निवेश करता है तो वह चाहता है कि वो उन ऑप्शन को सेलेक्ट करें जहां उसे ज्यादा रिटर्न मिले। वैसे तो निवेश के कई ऑप्शन मौजूद हैं पर SIP और PPF काफी पॉपुलर ऑप्शन है। आज हम आपको बताएंगे कि पीपीएफ और एसआईपी में से कौन-सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगा।

नई दिल्ली। निवेश के लिए आज कई स्कीम्स मौजूद हैं। लेकिन, जब बात निवेश की आती है तो सभी निवेशक चाहते हैं कि वह ज्यादा रिटर्न देने वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ऐसे में निवेश के SIP और PPF काफी पॉपुलर स्कीम हैं। पीपीएफ एक सरकारी योजना है तो एसआईपी स्टॉक मार्केट से जुड़ा है।

आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों स्कीम्स में से आपके लिए कौन-सा बेस्ट रहेगा।

पीपीएफ (PPF)

पीपीएफ (Public Provident Scheme) स्कीम एक सरकारी स्कीम है। इस स्कीम में निवेश करके आप मोटा फंड जमा कर सकते हैं। वैसे तो इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड और लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है पर निवेशक मैच्योरिटी के बाद भी इसे 5-5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इस स्कीम में 7.1 फीसदी का सालाना गारंटी रिटर्न मिलता है। इस स्कीम में आयकर अधिनियम के 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ भी मिलता है।

मैच्योरिटी पीरियड - 15 वर्ष

गारंटी रिटर्न- 7.1 फीसदी

एसआईपी (SIP)

एसआईपी (Systematic Investment Plan) शेयर बाजार से लिंक्ड होता है। इसमें वैसे तो इसमें औसत 12 फीसदी का रिटर्न मिलता है, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने किस सेक्टर के एसआईपी में निवेश किया है।

एसआईपी में कोई लॉक-इन पीरियड नहीं होता है। इसमें आप जब चाहें तब निवेश कर सकते हैं और कभी भी निकासी कर सकते हैं। एसआईपी में आपको हर महीने एक निश्चित अमाउंट का निवेश करना होता है। आपको बता दें कि आप एसआईपी में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (सी) के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं।

रिटर्न- औसत 12 फीसदी

कोई लॉक-इन पीरियड नहीं है

यह भी पढ़ें- 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस राज्य ने खोला खजाना, 27.5 फीसदी बढ़ेगी सैलरी

कौन-सी स्कीम है आपके लिए बेस्ट

अगर आप पीपीएफ में हर महीने 12,500 रुपये का निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी यानी 15 साल में आप 22,50,000 रुपये तक का निवेश कर चुके होंगे और आपको ब्याज के साथ 40,68,209 रुपये मिलेंगे।

हर सेक्टर को आम बजट से खास उम्मीदें, 23 जुलाई को होने जा रहा है पेश

यूनियन बजट 2024 अगले हफ्ते वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश होगा। इस बजट से आम जनता के साथ सभी सेक्टर को काफी उम्मीदें है। आम जनता को जहां एक तरह टैक्स छूट की उम्मीदें हैं। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के समर्थन की उम्मीद हैं। आइए इस लेख में कई दिग्गजों से जानते हैं कि आगामी बजट से क्या उम्मीदें हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

यूनियन बजट 2024 अगले हफ्ते वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश होगा। इस बजट से आम जनता के साथ सभी सेक्टर को काफी उम्मीदें है। आम जनता को जहां एक तरह टैक्स छूट की उम्मीदें हैं। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के समर्थन की उम्मीद हैं। आइए इस लेख में कई दिग्गजों से जानते हैं कि आगामी बजट से क्या उम्मीदें हैं।

नई दिल्ली। आगामी बजट में वित्त मंत्री से विभिन्न क्षेत्रों की अलग-अलग अपेक्षाएं हैं। शिक्षा क्षेत्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रमम के लिए अधिक धन चाहता है।

रियल एस्टेट क्षेत्र टैक्स इन्सेन्टिव्स और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए समर्थन की उम्मीद करता है। हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल रिसर्च के लिए अधिक बजट एलोकेशन चाहता है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कर छूट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहता है। कृषि क्षेत्र सब्सिडी और आधुनिक खेती के समर्थन की उम्मीद करता है। एमएसएमई क्षेत्र ऋण तक आसान पहुंच और कम अनुपालन बोझ की उम्मीद करता है।

कुल मिलाकर सभी सेक्टर ऐसी नीतियाँ चाहते हैं जो विकास को बढ़ावा दें, रोजगार सृजित करें और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करें।

बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को है बड़ी उम्मीदें

शहरीकरण की तेज़ रफ़्तार के साथ, रिटेल सेगमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए ग्रेड ए रिटेल स्पेस की भारी मांग है। यह सिर्फ़ मेट्रो शहरों के लिए ही नहीं बल्कि टियर 2 शहरों के लिए भी सच है, जहाँ पूरी तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर, ख़ास तौर पर कमर्शियल स्पेस में काम करने वाले सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार अपने आगामी बजट में नीतिगत स्तर पर कुछ पहल करके इसे सुनिश्चित करेगी।

भूमिका ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर उद्धव पोद्दार

इसके आगे वह कहते हैं कि हमारा मानना है कि अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट उपलब्ध होता है, तो इससे इस सेगमेंट को काफी फायदा होगा। इस सेक्टर को उद्योग का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग पर भी गौर किया जाना चाहिए। सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम भी स्थापित किया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो देश में रियल एस्टेट को बढ़ावा देंगे।

उद्योग के आसपास सकारात्मक भावनाओं के बावजूद, चुनौतियां बनी हुई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर प्राइस सेंसिटिव है और सीमेंट और स्टील जैसी इनपुट वस्तुओं पर कर अभी भी परियोजना की निर्माण लागत को बढ़ा रहे हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो इस पर गौर करेगी और सिंगल विंडो क्लीयरेंस की भी उम्मीद करते है। रियल एस्टेट देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है और इस क्षेत्र के लिए कोई भी लाभकारी कदम पूरे अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालेगा।

अश्विनी कुमार, पिरामिड इंफ्राटेक

सौरभ उपाध्याय, एमडी, ट्राइसोल रेड ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रियल एस्टेट सेक्टर एक महत्वपूर्ण विकास इंजन है, रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया जाना इसकी प्रमुख मांगों में से एक है। इस दर्जे से डेवलपर्स को कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने और कर प्रोत्साहन और छूट का लाभ मिल सकेगा, जो आर्थिक मंदी के समय में महत्वपूर्ण सहारा है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र ने मजबूती से पुनरुत्थान किया है और इस गति को बनाए रखने के लिए सरकार का समर्थन आवश्यक है।

रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार उद्योग का दर्जा और सिंगल विंडो क्लियरेंस की उसकी लंबे समय से लंबित मांगों पर गौर करेगी। विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती मांग के साथ यह सेक्टर बेहतर कर रहा है। सरकार को विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने और बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार लाने पर विचार करना चाहिए। इससे क्षेत्र की वृद्धि को बहुत लाभ होगा और देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। इसके अलावा, टैक्स में संशोधन भी उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक होगा जिस पर सरकार को आगामी बजट में विचार करना चाहिए क्योंकि यह पहली बार घर खरीदने वाले लाखों को प्रोत्साहित करेगा।

लैंडमार्क ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन, संदीप छिल्लर

नीरज शर्मा, एमडी, एस्कॉन इंफ्रा रियल्टर्स के अनुसार नीति आयोग की यह भविष्यवाणी कि भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर बाजार आकार तक पहुँच जाएगा, इसकी दीर्घकालिक संभावनाओं को उजागर करता है। सेक्टर सरकार से स्टील, सीमेंट और ईंधन की लागत को कम करने के उपायों की उम्मीद कर रहा है। उद्योग का दर्जा और सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने से डेवलपर्स को कम ब्याज दरों पर लोन प्राप्त करने और कर प्रोत्साहनों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। ये कदम क्षेत्र को काफी बढ़ावा देंगे और आगे के विकास को प्रोत्साहित करेंगे।

हम बजट 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ बड़े सुधारों की उम्मीद है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि होमबॉयर्स और निवेशकों को टैक्स लाभ मिलें, जैसे कि होम लोन के ब्याज भुगतान पर कटौती की सीमा बढ़ाना और निर्माणाधीन संपत्तियों पर जीएसटी कम करना, जिससे हाउसिंग की मांग बढ़ सकती है। परियोजना अनुमोदनों की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाना भी जरूरी है ताकि प्रगति बनी रहे। हम उन नीतियों के बारे में उत्साहित हैं जो न केवल सतत विकास को बढ़ावा देंगी बल्कि उद्योग की चुनौतियों का भी समाधान करेंगी, जिससे संबंधित क्षेत्रों में अधिक नौकरी के अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर, हम उम्मीद करते हैं कि आगामी बजट में ऐसी नीतियाँ होंगी जो सतत विकास को बढ़ावा दें और उद्योग की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करें।

श्री विकास भसीन, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर - साया ग्रुप

एक रियल एस्टेट विशेषज्ञ के रूप में, मैं आगामी भारतीय केंद्रीय बजट में कई प्रमुख उपायों की उम्मीद करता हूं जो इस क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बढ़ा हुआ बजट आवंटन, विस्तारित PMAY लाभ और घर खरीदने वालों के लिए बढ़े हुए कर लाभ मांग को बढ़ावा दे सकते हैं। पहली बार खरीदारों के लिए अधिक कर राहत, गृह ऋण ब्याज पर बढ़ी हुई कटौती और अतिरिक्त धारा 80EEA प्रोत्साहन निवेश को प्रोत्साहित करेंगे। निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए GST दरों को कम करने से लागत कम होगी और बिक्री बढ़ेगी।

मोहित मित्तल, मोर्स टेक्नो के सीईओ

एजुकेशन सेक्टर को हैं अधिक उम्मीद

अगर आर्थिक परिस्थितियाँ अनुकूल रहती हैं और सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देती है, तो हम 13% से अधिक की वृद्धि देख सकते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर समर्थन और शैक्षिक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाता है। इससे स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी एकीकरण और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए विभागानुसार धन का प्रबंध करना संभव होगा।

डीपीएस इंदिरापुरम की प्रिंसिपल प्रिया जॉन

वहीं क्रैक एकेडमी के फाउंडर और सीईओ नीरज कंसल ने कहा कि देश को शिक्षा में वैश्विक स्तर पर सुधार लाने के लिए मानव संसाधनों में निवेश और पूंजी व्यय को एकसाथ लाने की आवश्यकता है। आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 में, हमें उम्मीद है कि सरकार शिक्षा बजट को 13% से अधिक बढ़ाएगी, जिससे शैक्षिक ढांचा मजबूत होगा। इसके साथ ही, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग के लिए वित्तीय सहायता को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षा सेक्टर को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अधिक धन, स्किल डेवेलपमेंट प्रोग्राम में वृद्धि और इंडस्ट्रियल अकादमिया कोलैबोरेशन के लिए प्रोत्साहन की उम्मीद है। शिक्षा को अधिक सुलभ और किफायती बनाने तथा भविष्य के लिए कुशल कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता की आशा भी है। उम्मीद है आने वाले बजट में शिक्षा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

सैय्यद मसूद , एमडी हेरिटेज इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का कहना है

आगामी बजट में स्वास्थ्य देखभाल के लिए जीडीपी का 2.5 से 3.5 फीसदी आवंटित करने का लक्ष्य होना चाहिए।

बजट युवाओं, किसानों और हमारे राष्ट्र को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री से आगामी बजट में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ाने को प्राथमिकता देने का आग्रह करता हूं। आयुष्मान भारत या व्यापक बीमा कवरेज जैसी पहल के माध्यम से, प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होनी चाहिए।

यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशांबी चेयरमैन डॉ. पीएन अरोड़ा

इसके आगे डॉ. पीएन अरोड़ा कहते हैं कि भारत दुनिया भर में मरीजों की सेवा करने में सक्षम स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का दावा करता है। आगामी बजट में स्वास्थ्य देखभाल के लिए जीडीपी का 2.5 से 3.5 फीसदी आवंटित करने का लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर बढ़ सकें और जीएसटी में हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके किफायती उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करने और आवश्यक सेवाओं को छूट देने से सुलभ स्वास्थ्य देखभाल और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा, विशेष रूप से जीएसटी सुधारों के माध्यम से कराधान में निष्पक्षता सुनिश्चित करना इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

एमटीएनएल के बांड ब्याज का तत्काल भुगतान करने के लिए सरकार ने जमा किए 92 करोड़ रुपये

एक नई जानकारी सामने आई है जिसमें पता चला है कि सरकार ने एमटीएनएल के बांड बकाये के लिए 92 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कदम उठाया है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में ब्याज दायित्वों के लिए 64 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जाएगा जो अगस्त में देय होने वाले हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

एक नई जानकारी सामने आई है जिसमें पता चला है कि सरकार ने एमटीएनएल के बांड बकाये के लिए 92 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कदम उठाया है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में ब्याज दायित्वों के लिए 64 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जाएगा जो अगस्त में देय होने वाले हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) में संभावित ऋण संकट को टालने के लिए हस्तक्षेप किया है।

एक सरकारी सूत्र ने एमटीएनएल के बकाया बांड ड्यू के लिए 92 करोड़ रुपये के भुगतान की पुष्टि की है। इस तत्काल निधि को ब्याज भुगतान के लिए नामित एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा।

अगस्त में अतिरिक्त भुगतान की योजना

सरकार आने वाले दिनों में 64 करोड़ रुपये और आवंटित करके और सहायता देने का इरादा रखती है। इस भुगतान से अगस्त में परिपक्व होने वाले ब्याज दायित्वों को कवर करने की उम्मीद है।

बढ़ती वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही एमटीएनएल ने पहले 20 जुलाई को देय कुछ बांडों पर ब्याज भुगतान करने में असमर्थता की घोषणा की थी। यह स्थिति कंपनी के भीतर पर्याप्त धन की कमी से उत्पन्न हुई थी।

सरकारी गारंटी ने हस्तक्षेप को दी गति

प्रभावित बांड सरकारी गारंटी के साथ जारी किए गए थे, जिसका अर्थ है कि सरकार किसी भी चूक को कवर करने के लिए बाध्य है। संभावित चूक को रोकने और गारंटी को बनाए रखने के लिए, सरकार ने आवश्यक भुगतान करने के लिए कदम उठाया।

हाल ही में हुए ऋण संकट ने एमटीएनएल के चल रहे वित्तीय संघर्ष को उजागर किया है। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने ग्राहक आधार में लगातार गिरावट देखी है, जिससे घाटा बढ़ता जा रहा है।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। हालांकि एजेंसी वर्तमान में सरकारी गारंटी के कारण प्रभावित बॉन्ड पर स्थिर रेटिंग बनाए हुए है, लेकिन इसने संकेत दिया है कि यह भविष्य के घटनाक्रमों के आधार पर उचित रेटिंग कार्रवाई करेगी।

मिली अस्थायी राहत

सरकार के हस्तक्षेप से एमटीएनएल को अस्थायी राहत मिली है, लेकिन कंपनी की दीर्घकालिक वित्तीय सेहत चिंता का विषय बनी हुई है। इसकी वित्तीय गिरावट के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना इसकी भविष्य की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

स्पाइसजेट के शेयरों में शानदार तेजी, एक दिन पहले जारी किये थे तिमाही

स्पाइसजेट (SpiceJet) ने सोमवार को पिछले कारोबारी साल के आखिरी तिमाही के नतीजों का एलान किया था। कंपनी ने बताया कि मार्च तिमाही में स्टैंडअलोन मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। आज स्पाइसजेट के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। आइए इस लेख में स्पाइसजेट की तिमाही नतीजों के बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। प्राइवेट एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) के शेयर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर में 7 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी ने सोमवार को पिछले कारोबारी साल के आखिरी तिमाही के नतीजों का एलान किया था। स्पाइसजेट को मार्च तिमाही में शानदार मुनाफा हुआ।

कैसा रहा स्पाइसजेट का तिमाही नतीजा

मुनाफा: जनवरी-मार्च तिमाही में स्पाइसजेट का स्टैंडअलोन मुनाफा कई गुना बढ़कर 119 करोड़ रुपये हो गया। यह पिछले साल की इसी तिमाही में 16.85 करोड़ रुपये था।

रेवेन्यू: स्पाइसजेट ने शेयर बाजार को बताया कि मार्च तिमाही में कंपनी का राजस्व 20 फीसदी घटकर 1,719.37 करोड़ रुपये रह गया। मार्च 2023 की तिमाही में कंपनी का राजस्व 2,144.85 करोड़ रुपये था।

नेट लॉस: स्टॉक फाइलिंग के अनुसार कारोबारी साल 2023-24 के लिए स्पाइसजेट का नेट लॉस 409.43 करोड़ रुपये रहा, वहीं वित्त वर्ष 23 में एयरलाइन को 1,503 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

कितना है शेयर का भाव

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर स्पाइसजेट के शेयर 7.35 फीसद चढ़कर 60 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया। खबर लिखते वक्त कंपनी के 4.42 फीसदी की तेजी के साथ 58.36 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी ने कितना रिटर्न दिया? अगर इसकी बात करें तो पिछले एक साल में स्पाइसजेट के शेयर 89.60 फीसदी चढ़ें हैं। वहीं, बीते 6 महीने में कंपनी के शेयर ने नेगेटिव 10.38 फीसदी का रिटर्न दिया है। बीएसई की वेबसाइट के अनुसार स्पाइसजेट का एम-कैप (Spiccejet M-Cap) 4,632.69 करोड़ रुपये है।

अचानक क्यों बढ़ गई आतंकी घटनाएं? किसी की साजिश या आतंकवादी संघर्ष

परिवहन विशेष न्यूज

आगामी महीनों में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य में आतंकी घटनाओं में तेजी चिंताजनक है। अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद राज्य में निवेश आया है और विकास की गतिविधियां तेज हुई हैं। यह पड़ताल अहम मुद्दा है कि बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के बीच जम्मू में आतंकी हमले तेज करने के पीछे पाकिस्तान की क्या रणनीति है?

नई दिल्ली। आतंकी संगठन अब जम्मू क्षेत्र को निशाना बना रहे हैं। लगातार इस तरह के हमलों से साफ है कि आतंकियों ने इस क्षेत्र में अपनी जड़ें फिर से जमा ली हैं। भौगोलिक दृष्टि से समझें तो ज्यादातर हमले पीर पंजाल के दक्षिण क्षेत्र में हो रहे हैं। यह पूरा क्षेत्र घना पहाड़ी जंगल है और कुछ मीटर भी देखना संभव नहीं है। पाकिस्तान से आने वाले आतंकी इसका फायदा उठाकर सुरक्षाबलों पर हमला करते हैं और फिर जंगल में ही भाग जाते हैं और इस क्षेत्र में बने ठिकानों में छिपे रहते हैं।

वर्ष 2,000 के आसपास यह क्षेत्र आतंक का गढ़ बन चुका था। कश्मीर से अधिक हमले इसी क्षेत्र में होते थे। राजौरी-पुंछ से लेकर डोडा-किश्तवाड़ और रियासी में एक के बाद कई नरसंहार हुए और उसके बाद शासन चेता और सेना को आतंक के सफाए के लिए खुली छूट दी गई।

2004 में पुंछ में हिल काका पर ऑपरेशन सर्प विनाश को अंजाम दिया गया। अन्य जिलों में भी सेना की रोमियो फोर्स ने आतंकियों को खोज-खोजकर मारना शुरू कर दिया। उसके बाद इन आतंकियों को कोई ठौर नहीं मिली। उसके बाद लगभग दो दशक की शांति के बाद इस क्षेत्र में आतंकी न केवल जड़ें जमा चुके हैं बल्कि सेना के शौर्य को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं।

कैसे मिल रहे आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने?

आवश्यकता यह समझने की है- ऐसे क्या हालात बने कि हम इस क्षेत्र में अमन की रक्षा नहीं कर पाए। इस क्षेत्र में आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने कैसे मिल रहे हैं, जबकि यहां की मूल आबादी सदैव आतंक के खिलाफ संघर्ष में सेना का साथ देती रही है।

पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों के कारण ऐसे लोगों को नदी, नालों और खड्डों के आसपास लगातार बसाया गया, जिनकी भूमिका सदैव संदिग्ध रही है। इन्हीं नालों के आस-पास आतंकियों को ठिकाने मिल रहे हैं और वह वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से निकल जा रहे हैं।

क्या संघर्ष विराम का फायदा उठा रहा पाकिस्तान?

दूसरा बड़ा कारण यह है कि हमने पाकिस्तान के साथ साल 2021 में संघर्ष विराम किया और इसका फायदा लगातार पाकिस्तान उठा रहा है। चूंकि अब नियंत्रण रेखा शांत है और पाकिस्तान के लिए इस क्षेत्र में आतंकियों की घुसपैठ कराना सुगम हो गया है।

इस दौरान नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम का पाकिस्तान ने फायदा उठाया और एलओसी के उस पार तबाह हो चुके अपने प्रशिक्षण केंद्रों को फिर से सक्रिय कर दिया और लगातार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करता रहा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। यही वजह है कि एक समय जम्मू- कश्मीर में लगभग तबाह हो चुका आतंकी नेटवर्क फिर से सक्रिय हो चुका है।

शांत क्षेत्र में क्यों हो रहे आतंकी हमले?

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पीर पंजाल के उत्तर क्षेत्र अर्थात दक्षिण कश्मीर में हमने सुरक्षा घेरा इस तरह से कसे रखा कि आतंकी और उनके समर्थक कसमसा कर रह गए।

वहीं, शांत दिख रहे पीर पंजाल के दक्षिण क्षेत्र पर हमारी चौकसी कम होती गई। इस क्षेत्र में सुरक्षाबल पहले से ही कम थे। ऐसे में पाकिस्तान ने आतंकियों के अपने नेटवर्क को पहले राजौरी-पुंछ तथा डोडा जैसे जिलों में फिर से सक्रिय कर दिया।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र आतंकियों के लिए आश्रय स्थल रहे हैं। इन जंगलों में छिपकर आतंकी हमलों को अंजाम देते थे। करीब दो दशक पूर्व भी यह क्षेत्र आतंक का गढ़ रहा था और कश्मीर से अधिक हमले इस क्षेत्र में होते थे। अब रियासी में निर्दोष महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया।

फिर कठुआ में सेना के वाहन पर हमला चिंता की बात है। अब समय ठोस निर्णय लेने का है। राजौरी, पुंछ के बाद रियासी और कठुआ के हमले बताते हैं कि सेना को और एक ओर निर्णायक प्रहार के लिए छूट देनी होगी। इस बार निर्णायक कार्रवाई हो और ऐसी हो कि पाकिस्तान कुछ भी करने से पहले सौ बार सोचे।

निति अयोग रेपोट मे ओडिशा ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वरः पिछले कुछ वर्षों में, ओडिशा ने समग्र विकास का नेतृत्व करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ओडिशा के इस परिवर्तन को देश और देश के बाहर विभिन्न संगठनों द्वारा अलग-अलग समय पर मान्यता दी गई है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंटेक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जब यह रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के लिए प्रकाशित की गई, तो ओडिशा इस क्षेत्र में अग्रणी श्रेणी में है। SDG का पहला लक्ष्य, गरीबी उन्मूलन (कोई गरीबी नहीं)। इस क्षेत्र में ओडिशा को 73 अंक मिले, जबकि देश की कुल संख्या 72 है। कहा जा रहा है कि निवर्तमान सरकार ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में व्यापक कदम उठाए हैं और रिपोर्ट में इसकी झलक मिलती है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने खुशी जताई है।

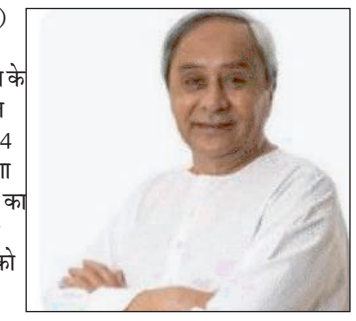

खटीक समाज शाहपुरा की बैठक सम्पन्न हुई

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा जिले के खटीक समाज की समृध्द एवं वृक्षारोपन योजना एवं कुरीतियो के बारे में बैठक सोमवार को साम को पांच बजे खटीक समाज धर्मशाला में सम्पन हुई। जिसमे समाज मे व्याप्त कुरीतियों के बारे में चर्चा हुई आज कल शादियों में प्रीविडिंग का चलन चल रहा है जिसमे लड़के-लडकिया शादी से पहले मिलते है और फ़ोटो खिंचवाते है जो कि यह गलत है और मृतुभोज में एक खाना रखने का निर्णय लिया तथा शाहपुरा जिला हो जाने पर खटीक समाज के छात्रावास की भी मांग रखी गई एवं खटीक समाज अम्बेडकर लाइब्रेरी में कम्पीटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए बुक्स की व्यवस्था के लिए भी चर्चा की गई और समाज के कमजोर बच्चे जो 10-12 में पढ़ते है उनके लिए निःषुल्क कोचिंग पढ़ाने के लिए भी चर्चा की गई। यह बैठक खटीक समाज समृध्द के अध्यक्ष सीताराम खींची, संरक्षक राजमल खींची, सह सचिव छगन खींची व रतन पहाड़िया और शाहपुरा अध्यक्ष नवीन चावला, पूर्व अध्यक्ष छगन बाछड़ा, पूर्व धानेश्वर अध्यक्ष कालूराम सोलंकी, रामेश्वर सोलंकी, रमेश टेपण, गोवर्धन सोलंकी, राजेश सोलंकी, जगदीश खींची, रतन पहाड़िया और राजेंद्र चन्देरिया उपस्थित थे।

21 हमलों में गई 43 जवानों की जान, क्या आतंकियों के जरिए भारत पर दबाव

परिवहन विशेष न्यूज

कश्मीर में हिंसक गतिविधियों पर लगाम लगने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट अब फिर से राष्ट्रवादी जम्मू को निशाना बना रहे हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सितंबर 2021 से अब तक आतंकी जम्मू संभाग में 21 से अधिक हमलों को अंजाम दे चुके हैं। इन हमलों में सेना के 43 जवानों को सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा है।

नई दिल्ली। जम्मू क्षेत्र में लगातार हो रहे आतंकी हमलों से चिंता बढ़ रही है कि कहीं जम्मू भी दूसरा कश्मीर तो नहीं बनने जा रहा। कश्मीर में हिंसक गतिविधियों पर लगाम लगने के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट अब फिर से राष्ट्रवादी जम्मू को निशाना बना रहे हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सितंबर 2021 से अब तक आतंकी जम्मू संभाग में 21 से अधिक हमलों को अंजाम दे चुके हैं और इन हमलों में सेना के 43 जवानों को सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा है।

यह साजिश नई नहीं हैं। कश्मीर में हिंसा की शुरुआत के साथ ही पाकिस्तान और आईएसआई जम्मू को अशांत बनाने की निरंतर साजिशें रचते रहे हैं। 31 जनवरी 1995 की एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि आईएसआई ने वर्ष 1995 को 'जम्मू संभाग का वर्ष' घोषित किया था। जम्मू में हिंसा फैलाने और पूरे क्षेत्र को अशांत घोषित करने के लिए नशा माफिया के माध्यम से 50 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

उसी दौरान खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई का हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकियों को भेजा गया एक संदेश भी पकड़ा था, जिसमें तब के राज्य के पुलिस प्रमुख एमएन सब्रवाल और राज्यपाल के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल एमके जैकी पर आत्मघाती हमले के लिए पांच करोड़ रखे गए थे। पाकिस्तान की जम्मू नीति को समझने के लिए थोड़ा अतीत को टटोलना होगा।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की बार-बार किरकिरी

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की कश्मीर पर बार-बार किरकिरी और उसके दुष्प्रचार का एजेंडा विफल होने के बाद से पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी जम्मू क्षेत्र को हिंसा की आग में झोंकने को बेताब दिखे। वर्ष 1994 इसमें अहम है। उस वर्ष जेनेवा में मानवाधिकार कांफ्रेंस में दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए थे।

पहला भारत की कूटनीति के चलते पाकिस्तान को कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन पर अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इसके अलावा यूरोपीय संघ और पनुन कश्मीर समेत कुछ अन्य सामाजिक संगठनों ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार के एजेंडे की पूरी तरह हवा निकाल दी।

जेनेवा में मिली हार के बाद से ही आईएसआई आतंकवाद को जम्मू क्षेत्र तक ले जाने के लिए अपने नेटवर्क के विस्तार में जुट गई। साजिश थी कि आतंकी हिंसा के जरिये शांत जम्मू क्षेत्र में हिंदू व मुस्लिम आबादी में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया जा सके। साजिशें बहुत हुईं पर जम्मू ने विघटनकारी एजेंडे को नकार दिया।

तीन दशक बाद क्यों ISI और आतंकी जम्मू का रुख कर रहे?

तीन दशक बाद एक बार फिर आईएसआई और उसके पाले हुए आतंकी जम्मू का रुख कर रहे हैं। इस बार चुनौती और भी बड़ी दिख रही है। चूंकि, पाकिस्तान की तैयारी बड़ी है। आतंकी और आईएसआई के गुर्गे जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों में अपने मजबूत ठिकाने बना चुके हैं।

पाकिस्तान की बदली नीति के ये कारण हैं...

1- पहला बड़ा कारण यह है कि गुलाम जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार की नीति पाकिस्तान को डरा रही है। कश्मीर को शांत देखकर पाकिस्तान को डर है कि भारत गुलाम जम्मू-कश्मीर को कभी भी वापस ले सकता है। उसके कब्जे वाले क्षेत्र में उठ रहे विरोध प्रदर्शनों से उसकी चिंता बढ़ना लाजमी भी है।

ऐसे में जम्मू संभाग में हिंसा फैलाकर वह भारत पर दबाव बनाना चाहता है कि आप गुलाम जम्मू-कश्मीर लेने से पहले अपने जम्मू को सुरक्षित करो। यही वजह है उसने सबसे खूंखार और प्रशिक्षित विदेशी आतंकियों को अत्याधुनिक हथियारों के साथ उतारा है और वह लगातार हमलों को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं।

2- दूसरा कारण है कि जम्मू संभाग का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के माध्यम से जुड़ा है। महत्वपूर्ण यह भी है कि यह क्षेत्र सदैव शांति की उम्मीद जगाता है और यहां सांप्रदायिक भाईचारा कायम है। पाकिस्तान की तमाम साजिशों और हिंसा फैलाकर सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव बढ़ाने के प्रयासों का जम्मू के लोगों ने धैर्य से मुकाबला किया और शांति कायम रख कर पाकिस्तान के एजेंडे को विफल बना दिया।

3- तीसरा बड़ा कारण है कि जम्मू सदैव राष्ट्रवादी ताकतों का केंद्र रहा है और प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का समर्थक रहा है। यह बात पाकिस्तान को कभी रास नहीं आई।

4- चौथा कारण है कि जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों में आतंक के सफाए के लिए पर्याप्त सैन्य और सुरक्षा बल मौजूद नहीं थे और आतंकियों को इन क्षेत्रों में डेरे बनाने का अवसर मिल गया।

5- पांचवां बड़ा कारण है कि जम्मू प्रदेश की आर्थिकी का केंद्र रहा है और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता रहा है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए करीब एक करोड़ श्रद्धालु प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में पहुंचते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। रियासी में श्रद्धालुओं को निशाना बनाना, कठुआ में सेना के वाहनों पर हमला और पिछले तीन वर्षों में जम्मू क्षेत्र में बार-बार निर्मम प्रहार के माध्यम से पाकिस्तान और उसके एजेंट भारत को हजारों घाव देने की मंशा रखते हैं।

स्वधर्म संदेश

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा में पारदर्शिता और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को सुनिश्चित व्यवस्था देने के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए आदेश दिया गया है। जिसका बड़े पैमाने पर शिक्षकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। विरोधी शिक्षक यह प्रमाणित करने में लगे हैं कि सरकार की यह व्यवस्था इसीलिए सही नहीं है की समय पर स्कूल पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि लोगों को काफी दूर से स्कूल जाना पड़ता है। रास्ते में क्षेत्रीय समस्याओं के कारण सड़क भीड़ यातायात की परेशानियां होती है।

शिक्षकों द्वारा सरकार के इस नियम का विरोध सामाजिक अराजकता का एक जिंदा उदाहरण है। समाज अराजक हो गई है। अनियमित हो गई है। कर्तव्य विमुख हो गई है। इस विरोध से यही प्रमाणिक होता है। आप वेतन लेते हैं आपके बच्चों को नियमित ढंग से ज्ञान देने की जिम्मेदारी है। प्राकृतिक रूप से भी जो जिस काम में लगा है अगर उसे काम को ईमानदारी से कर्तव्य से करेगा तो निश्चित उसका प्रतिफल देश और समाज को लाभ देगा लेकिन जब समाज में लोग सिर्फ शारीरिक के पारिवारिक और निजी सुख सुविधा की व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए अपने सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाता है तभी इस तरह की अवस्था को ताकत मिलती है। सरकार अगर जनहित ऐसा प्रयास कर अच्छा करने करने का प्रयास करती है तो स्वार्थी मानसिकता के सामाजिक गतिविधियों को निश्चित ही परेशानी होगी और जब सामाजिक अराजकता संगठित विद्रोह की स्थिति में गलत के साथ मिल जाता है तो समाज हित में काम करने वाली सरकार के लिए परेशानी बन जाती है क्योंकि भारत की चुनाव व्यवस्था में गलत के वर्चस्व की वजह से समाज जब गलत को अपने जीवन का आचरण बना लेती है तो देश विरोधी पार्टियों को ऐसे गलत व्यवस्था को ताकत देने में जनता का सहयोग मिल जाता है। योगी द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए जनहित में बहुत बड़े सुधार के बाद भी लोकसभा चुनाव में सेवा काम और विकास इसीलिए हार गया क्योंकि सामाजिक आचरण लोभी स्वार्थी अवसरवादी जातिवादी भ्रष्टाचारी अराजकता का पक्षधर बनकर लूटपाट की मनोवृत्ति को आत्मसात कर लिया है।

जब तक सामाजिक जीवन में बने हुई इस सोच का अंत नहीं होता है तब तक देश और समाज का भला संभव नहीं है इसलिए योगी और मोदी समाज को अनुशासित बनाने के लिए वे सारे कदमों को जमीनी अस्तित्व देने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। ऐसा मेरी समझ है। ये लोग सरकार बचाने के लिए नहीं राष्ट्र रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। कोई कुछ भी कहें उसे ऐसे लोगों को जो आध्यात्मिक है जिनका लक्ष्य मानवता के कल्याण को समर्पित है। वैसे लोगों के जीवन पर और व्यवहार पर गलत का कोई असर नहीं पड़ता है।

डॉ राजू कुमार विद्यार्थी
सामाजिक राजनीतिक विचारक

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय सदस्यता अभियान इस सत्र 55% बढ़ोतरी....

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाहपुरा की जिला बैठक आदर्श विद्या मंदिर कोठार मोहल्ला में संपन्न हुई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रवासी कार्यकर्ता जिला प्रभारी प्रदेश सचिव भंवर सिंह राठौड़ रहे कार्यक्रम के अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय महेश शर्माने की जिला मंत्री संजीव शर्मा ने बताया कि सभी उप शाखों के अध्यक्ष मंत्री व कोषाध्यक्ष ने बैठक में भाग लिया राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाहपुरा की वर्तमान सदस्यता कुल 3108 रही गत वर्ष की सदस्यता 2007 थी इस बार 55% बढ़ोतरी हुई उपशाखा शाहपुरा की सदस्यता 916 जहाजपुर की सदस्यता 1261 बनेड़ा की सदस्यता 250 कोटडी की सदस्यता 302 व फुलिया की सदस्यता 369 रही प्रभारी को खाली भरी हुई रशीद बुके सदस्यता सूची पांच प्रतियो में तैयार कर सौपी गई सदस्यता राशि का 25% प्रदेश को 25% जिला को और 50% ब्लॉक के नाम ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया जिला प्रभारी भंवर सिंह राठौर ने प्रत्येक उप शाखा पर 21 जुलाई को गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रभारी नियुक्त के जिसमें शाहपुरा प्रभारी महेश शर्मा कोटडी प्रभारी अमर सिंह चौहान बनेड़ा प्रभारी सांवरिया जाट जहाजपुर प्रभारी इंद्रा धूपिया फुलिया प्रभारी संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा शाहपुरा जिले में 4650 पेड़ पौधे लगाए गए जिला अध्यक्ष महेश शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षक समस्याओं को लेकर संगठन द्वारा शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा जिला शिक्षा अधिकारी शाहपुरा से समय-समय पर वार्ता की गई बैठक में शाहपुरा अध्यक्ष अमर सिंह चौहान उप शाखा जहाजपुर अध्यक्ष पवन जोशी उपशाखा फुलिया अध्यक्ष सत्यनारायण सुथार जिला कोषाध्यक्ष सांवरिया जाट जिला सचिव मुकेश कुमावत जिला महिला मंत्री इंद्रा धूपिया शाहपुरा उपशाखा महिला मंत्री सुनीता समदानी महिला उपाध्यक्ष नयन बाल सोमानी उपाध्यक्ष पुरुष संजय त्रिपाठी नवरत्न मल बगड़िया कोटडी संयोजक दुर्गेश शर्मा सहसंयोजक पुष्पेंद्र काबरा प्रदेश प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश शर्मा देवीलाल कुमावत राजेश मीणा मनोज मीणा नयन नयन बोलिया राकेश सोनी पंकज सोनगरा पवन कुमार गगरानी गगरानी उपस्थित रहे मंच संचालन मुकेश कुमावत ने किया।

दोस्ती के के रंग

विजय गर्ग

दोस्त का कोई तय मतलब नहीं होता है और अगर मतलब होता तो दोस्ती होती ही नहीं। दोस्ती इस संसार का ऐसा नाता है जो किसी भी औपचारिकता का मोहताज नहीं है, किसी प्रकार के बंधन का पर्याय नहीं है। अच्छे दोस्त होना मोक्ष पाने के बराबर है। रिश्ते-नाते मुसीबत में साथ तो आते तो हैं, लेकिन उनमें किंतु-परंतु बहुत होते हैं। वहीं दोस्ती सारी किंतु-परंतु से ऊपर होती है। जो कोई आगे-पीछे नहीं सोचता, बस खुशी हो या गम, बगैर बुलाए, बगैर किसी तामझाम के जो आ जाए, वही दोस्त और ईश्वर होते हैं । ऐसा कहते हैं कि दोस्ती हृदय से हृदय का बंधन होता है और सच्चा दोस्त परेशानी आने से पहले ही मौजूद हो जाता है । कुछ लोग अपने दोस्ताना मिजाज के लिए ही बने होते हैं। मित्रता का विज्ञान ही दिल से चलता है, जहां गुणा- भाग, घटाव का स्थान नहीं होता है, सिर्फ जोड़ होता है । इतना ही गणित आता है दोस्तों को । वे एक और एक ग्यारह करना जानते है, दो और दो पांच तो कभी आठ कर देते हैं, पता ही नहीं चलता । रसायन भी इतना ही जानते है कि जो पदार्थ घुलनशील हैं, वे ही दोस्तों को याद रहते हैं। दोस्त नमक की तरह होते हैं । न हों तो खाने का स्वाद ही नहीं रहता है । उनका अर्थशास्त्र अलग ही होता है और कहता है, 'तू रख अभी, जब तेरे पास आएगा तब दे देना ।'

दोस्त सिर्फ आवरण को प्रभावित नहीं करते, वे अंतरतम तल तक जाकर वह सब कुछ जानते हैं जो शायद परिवार के लोग भी नहीं जानते । उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि दोस्त की इस

समय जरूरतें क्या हैं । ऐसा अनुसंधान कहते हैं कि अगर मन में अवसाद है तो वह दोस्तों की संख्या पर निर्भर करता है । 'प्रोसीडिंग्स आफ रायल सोसायटी' जर्नल में प्रकाशित शोध दोस्ती के बारे में नई बात सामने रखता है। शोध में ऐसे दो हजार विद्यार्थियों को शामिल किया गया, जिनमें अवसाद के लक्षण दिखे । सामने आया कि जिन विद्यार्थियों के पास दोस्तों की संख्या बड़ी थी, उनमें अवसाद के लक्षण घटे । इनमें दोगुना तेजी से सुधार की संभावना देखी गई । अमेरिका में हुई एक और शोध के मुताबिक, अकेलापन अवसाद बढ़ाने के साथ सेहत को भी प्रभावित करता है ।

दरअसल, दोस्तों का दायरा हमारी उम्र बढ़ाता है और हमें खुश भी रखता है । दोस्ती हमेशा प्रेरणा देती है और हमें एकाकीपन से परे धकेलती है। जहां मौन हो वहां अगर दोस्त हो तो भी वह उस मौन को पढ़ लेता है । वे उन भावनाओं, अपनापन, खुशी, गम सबको पढ़ लेते हैं और वैसे ही सहयोग देने लगते हैं। बचपन के दोस्त तो ऐसे होते जो हमारी रग-रग से वाकिफ होते हैं और हमें चिढ़ाए बगैर नहीं मानते । ब्रिटिश मानव विज्ञानी और शोधकर्ता राबिन डनबार की शोध कहती है कि एक इंसान डेढ़ सौ से अधिक दोस्तों से दोस्ती नहीं निभा सकता। इनमें से इंसान के दिल के करीब कुछ ही दोस्त होते हैं। सबसे अच्छे दोस्त कितने होते हैं, इस पर राबिन का कहना है कि एक इंसान भले ही डेढ़ सौ दोस्तों के दायरे को निबाह सकता है, लेकिन मात्र पांच दोस्त ही ऐसे होते हैं, जिनसे वह अपनी हर बात साझा कर सकता है। जर्नल 'साइकोलाजिकल साइंस' में प्रकाशित शोध के मुताबिक, जो लड़के बचपन में अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, जब वे तीस वर्ष के होते हैं तो उनका रक्तचाप और 'बाडी मास इंडेक्स' कम रहता है। अमेरिका की टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के जेनी कंडिफ का कहना है, 'शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि शुरुआती जीवन का वयस्क होने पर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है । बचपन के हमारे दोस्त बड़े होने पर भी हमारी सेहत को फायदा पहुंचाते हैं।'

जीवन में कुछ रिश्ते हमें ऊपर वाला ही बनाकर देता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता हम नीचे आकर स्वयं चुनते हैं। कई शोध में यह सिद्ध भी हो चुका है कि अकेले रहने वाले लोगों के शरीर में कार्टिसोल नाम का तनाव हार्मोन तेजी से बनता है, जिसकी वजह से उन्हें तनाव से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। वहीं जिन लोगों के पास दोस्त होते हैं, जो ज्यादातर समय दोस्तों के साथ बिताते हैं, उनके तनाव हार्मोन कम हो जाते हैं । वे न सिर्फ बुरे वक्त में काम आते हैं, बल्कि हमें दिमाग से भी तेज बनाते हैं । यह सच है कि जिनके पास दोस्त हैं, वे लोग बाकी लोगों के मुकाबले दिमागी तौर पर ज्यादा जवान और तेज होते हैं। एक शोध के मुताबिक, यादों, भावनाओं और प्रेरणाओं को महसूस करने वाला दिमाग का हिस्सा स्पष्ट रूप से उम्र के साथ प्रभावित होता है। लोगों के दिमाग के इस हिस्से में सामाजिक संबंध संरक्षित रहते हैं ।

दरअसल, दोस्ती का एक ही नियम है कि उसका कोई नियम नहीं है। बगैर नियम के जो चले और उसमें चार चांद लगा दे वही दोस्ती का आयाम होता है। वैसे हर दोस्ती अपने आप में एक मिसाल होती है, क्योंकि कोई भी दोस्ती की तुलना दूसरी दोस्ती से नहीं की जा सकती। हर दोस्ती में कुछ नया ही मिलेगा, कुछ अतरंगी मिलेगा। जितने रंग दोस्ती के होते हैं, उतने रंग तो शायद कुदरत ने भी नहीं बनाए

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक
स्तंभकार मलोट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail .com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023